स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–21, अंक–8, श्रावण–भाद्रपद 2070, अगस्त 2013

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार उपभोक्ता वस्तुओं, टेलीकॉम, पावर प्लांट और अन्य परियोजना वस्तुओं (खासतौर पर चीन से) के आयातों पर पाबंदी लगाएं। सोना–चांदी के आयातों पर प्रभावी नियंत्रण लगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों पर तीन साल का लॉक–इन पीरियड का प्रावधान लागू किया जाए. . .

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा

मजबूरी के नाम पर विदेशियों का शिकंजा बढ़ाती सरकार
– स्वदेशी संवाद /4

गरीबी

गरीब की गरीबी के साथ एक बार फिर भद्दा मजाक
– डॉ. अश्विनी महाजन /7

कृषि : कृषि संकट को बुलावा
– देविन्दर शर्मा /10

अर्थव्यवस्था :

अपने रुपए को आप बचाइए
– आलोक पुराणिक /12

बहस : मिड डे मील – बन रही है मौत की खुराक
–डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल /14

समस्या

राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़
– बलवीर पुंज /17

लेख : स्वतंत्रता संग्राम में किसानों का योगदान
– उमेश प्रसाद सिंह /24

धरोहर : रामसेतु का भविष्य. . .?
– पुष्करलाल पुराणिक /26

विचार :

हमारे दर्शन में है भारत के पतन की जड़ें
–डॉ. भरत झुनझुनवाला /28

सुरक्षा : बिलबिलाएं नहीं संयम से लें काम
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /30

पर्यावरण : कहीं सूखा – कहीं बाढ़ क्यों?
– भारत डोगरा /31

रपट

डेयरी क्षेत्र को बचाने की दरकार **/33**

किसानों को मिले अस्थायी बिजली कनेक्शन /34

एफडीआई की खुली छूट का निर्णय जन–विरोधी /35

देश की सुरक्षा को दांव पर न लगाए केन्द्र सरकार /35

चीन की चुनौतियां /36

पाठकनामा

आखिर माफियों के साथ नेताओं की साठगांठ कब तक

आज दिल्ली से सटे नोएडा रेत माफिया की चर्चा पूरे देश में हो रही है। देखा जाए तो यह माफिया केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में रेत के अलावा अन्य तस्करी के धंधों में लिप्त हैं। प्राकृतिक संसाधनों की लूट के हिसाब से देखें तो भू–माफिया, जंगल माफिया, तेंदू पत्ता माफिया, आयरन–खनिज–कोयला माफिया, मिट्टी माफिया इत्यादि; ये माफिया देश की संपत्ति के साथ–साथ प्रकृति का भी दोहन करते हैं। इन धंधों की जब परतें खुलती है तो बड़े–बडे अधिकारियों के साथ–साथ नेताओं के रिश्तेदारों का नाम इन धंधों में पाया जाता है। परन्तु कार्यवाही के नाम पर सभी राज्य सरकारें चुप्पी साध लेती हैं। अगर कोई ईमानदार अफसर इन धंधों को रोकता है तो सरकार उस अफसर को ही सरकारी पद से हटा देती है। जहां नेता ईमानदारी का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं वहीं दूसरी तरह जब उनके करीबी रिश्तेदारों के कारोबार पर कोई आंच आती है तो तुरंत अपना चोला बदल लेते है। फिर ईमानदार अफसरों पर गाज गिरती है या फिर राज्य सरकारें चुप्पी साध लेती है। आज देश को जरूरत है कि नेता अपने पद को ईमानदारीपूर्वक देशहित में पालन करें तभी माफिया राज से मुक्ति मिल सकती है।

– दिपेश भण्डारी, सुशांत लोक, गुड़गांव

क्यों होता है अवैध खनन, अवैध कालोनियों का निर्माण

युवा आईएएस अधिकारी और गौतमबुद्ध नगर जिले के सदर क्षेत्र की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर उत्तर प्रदेश सरकार (सपा) की माफियों के साथ सांठगांठ की पोल तो खुल गई है परन्तु यहां एक बात पर गौर करने लायक है आखिर क्यों यमुना खादर से बालू का अवैध खनन होता है। समाजवादी यूपी सरकार कहती है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि ऐसा उनके राज्य में हो रहा है अगर हो रहा है तो कार्यवाही की जाएगी। जरा गौर कीजिए जब अवैध कालोनियां काटी जाती है तब पुलिस और सरकारी अधिकारी इन बिल्डरों से पैसा वसूल करते हैं फिर भी सरकार चुप बैठती है। जब अवैध कालोनियों में खरीददार मकान बनता है तो तुरंत पुलिसकर्मी वहां पहुंचकर अवैध निर्माण को बताकर उससे रिश्वत लेता है। अगर आपकी बाईक या कार चोरी हो जाए तो पुलिसवालों को उसे ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे लेकिन अवैध निर्माण जैसे ही शुरू हुआ तभी पुलिसकर्मी या अन्य अधिकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। कमाल की बात है सरकार को पता ही नहीं चलता। जब एक ईमानदार अधिकारी ने इस पर कार्यवाही की तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कई बार हमारे पर्यावरणविदों ने बताया है कि बालू के अवैध खनन से कभी भी बाढ़ के समय यमुना शहर की तरफ अपनी दिशा बदल सकती है। समय रहते अगर अवैध कालोनियां और अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो एक दिन उत्तराखंड की तरह गौतमबुद्ध नगर जिले में भी जान–माल का भारी नुकसान हो सकता है।

– राकेश कुमार मीडियाअपार्टमेंट, अभयखण्ड–4, इंदिरापुरम

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

देश में हर तरह का तंत्र मौजूद है लेकिन जनतंत्र नहीं। देश को सरकारी, राजनीतिक और अफसरशाही तंत्र से मुक्ति की जरूरत है।

– अन्ना हजारे

गुरु तत्व एक सिद्धांत है। गुरु एक तत्व है – आपके भीतर की गुणवत्ता है। यह एक शरीर या आकार में सीमित नहीं है।

– श्रीश्री रवि शंकर

सीमा पर भारतीय सैनिकों की हत्या भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यह साबित करे कि उनका अपनी सेना पर नियंत्रण है, तब भारत को पाकिस्तान के साथ अगले दौर की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए।

– राम माधव

सीमा पर जवानों की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है और सरकार को तत्काल पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर उसे करारा जवाब देना चाहिए।

– लालकृष्ण आडवाणी

आज आतंकवाद पर हावी रहने की जरूरत है क्योंकि अलकायदा के शीर्ष स्तर के नेतृत्व को खत्म करने के बावजूद चरमपंथ अभी कायम है।

– बराक ओबामा

देश मजबूत नेता चाहता है। नरेन्द्र मोदी के रूप में भाजपा को वाजपेयी के बाद पहली बार कोई मजबूत नेता मिला है।

– पृथ्वीराज चव्हाण

संपादकीय

भूख से वोट का सौदा

16 जुलाई 2013 को भारत सरकार ने गृहमंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की रत्ती भर परवाह न करते हुए देश के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में या तो एफडीआई लागू कर दी या एफडीआई की निवेश सीमा (कैप) को बढ़ाने का फैसला ले लिया। देश की सुरक्षा के प्रति इतनी संवेदनहीनता रखती हुई इस सरकार से यह अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है कि वह गरीबों के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन चारों तरफ से घोटालों में फंसी और आर्थिक क्षेत्र में निकम्मी साबित हुई सरकार किसी तरीके से दुबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या–क्या हथकंडे अपना सकती है, वह इस बात से साबित होता है कि नए संसद सत्र की शुरूआत से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पत्रकारों को कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराना है। उसके पहले सप्रंग की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दे चुकी थी। सरकार की पीठ पर सवार होकर कांग्रेस देश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर ही है कि उसके लिए भूखी जनता को खाने का हक देना जीवन मरण का प्रश्न है। कांग्रेस अपनी सारी संजीदगी और गंभीरता इसी मुद्दे पर उड़ेल देना चाहती है। कारण? क्या सचमुच कांग्रेस जनता के प्रति इतनी सहानुभूति रखती है, कि विश्व बैंक की चेतावनी और दरकती अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज करके भी एक 'ऐतिहासिक' कानून लाना चाहती है, जिसके तरह भोजन की गारंटी न होने पर कोई भी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। यह जानते हुए भी कि यदि इस योजना को इसकी मूल भावना के अनुसार लागू किया गया तो इसका आर्थिक असर हमारे विकास दर पर भी पड़ेगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जानते हैं कि बेकाबू अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जिस तरह की दिक्कतें सरकार के सामने आ रही है, और यदि उसे और बढ़ने दिया गया तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी। लगातार कड़ी मौद्रिक नीतियों के कारण देश का व्यापार और उद्योग बहुत बुरे दौर में पहुंच गया है। जहां हर क्षेत्र से नकारात्मक खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री पूरी तरह असहाय दिख रहे हैं। फिर जीडीपी के तीन फीसदी के बराबर खर्च करने की योजना को लागू करने के लिए कांग्रेस इतनी जल्दीबाजी में क्यों है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने इस योजना का नाम गेम चेंजर दिया है। यानी कांग्रेस यह मानती है कि केवल इस योजना के नाम पर वह चुनाव की बैतरणी पार कर सकती है। जिस तरह यूपीए–2 मनरेगा और किसानों की कर्जमाफी के नाम पर आई, उसी तरह यूपीए–3 खाद्य सुरक्षा के नाम पर आ जाएगी। फिर सरकार में शामिल कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि यूपीए–2 में जितने घोटोले और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, उसकी काट के लिए उनके पास यदि कुछ नहीं है तो फिर क्यों न एक बार देश की अर्थव्यवस्था को ही दाँव पर लगाकर चुनाव जीत लिया जाए। संसद के पिछले सत्र में जिस तरह विपक्ष भ्रष्टाचार के नाम पर हमलावर रहा और पूरे देश में एक सरकार विरोधी माहौल बनाने में कामयाब रहा उससे भी निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा विधेयक से भी बढ़िया ढाल क्या हो सकती है, और हुआ भी यही। भाजपा राजनीतिक नुकसान की आशंका के चलते ही खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सरकार का साथ देने को तैयार हो चुकी है। राजनीतिक कलाबाजी और शह मात के खेल के बीच यह मूल प्रश्न तो रह ही जाता है कि कांग्रेस आखिर भोजन के अधिकार वाले कानून के प्रति कितनी संजीदा है। यदि वास्तव में है तो पहला प्रश्न यही उठता है कि सोनिया गांधी ने आखिर इस कानून को अपने राजनीतिक तरकश के आखिरी तीर के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? जबकि पांच वर्ष पहले ही कांग्रेस ने इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया था। आखिर किसके हित के लिए पांच साल लोगों को इस अधिकार से वंचित किया गया भूख के लिए बच्चों तक को बेचने पर बिवश किया गया। जिस समय किसान लगातार आत्म हत्या कर रहे थे, लोग बेरोजगारी के कारण दरबदर ठोकरे खा रहे थे, उस समय को इस कानून को लागू करने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं माना गया। सराकरी आकड़े ही बताते हैं कि पिछले 16 साल में देश में 25 लाख ग्रामीण या किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस का यह बर्ताव उस साहूकार की तरह है जो अपने ग्राहक को विपत्ति में फंसा देखकर खुश होता है और फिर से अपनी शर्तों पर कर्ज देता है। सोनिया गांधी के रणनीतिकारों ने यही सलाह दी है कि भूख का वोट से सौदा करने के लिए अच्छा रहेगा कि यह कानून चुनाव के माहौल में आए। देश में दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल देने की परंपरा कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ और दक्षिण के प्रदेशों ने इसे बहुत पहले ही लागू कर दिया था। अन्य प्रदेशों में भी बीपीएल कार्ड के जरिए सस्ते अनाज का प्रावधान है। फिर से इसे राष्ट्रव्यापी योजना बनाने की अचानक जरूरत क्यों हो गई। शायद इसलिए कि यह योजना चुनावी नारा बन सके। हर मोर्चे पर विफल मनमोहन सिंह के लिए यह योजना फेस सेविंग की तरह इस्तेमाल हो सकती है। जिस पार्टी के सबसे 'काबिल' नेता राहुल गांधी जब यह कहें कि गरीबी कुछ नहीं मानसिक सोंच है, उसे भूख से लड़ने–मरने वालों की वास्तविकता कहां पता है। जिस पार्टी के नेता गरीबी रेखा को वास्तविकता से साथ तौलने को तैयार न तो। कोई 12 रुपये में तो कोई पांच रुपये में भर पेट भोजना का दावा करता हो उसे कैसे मालूम हो कि देश में लोगों की स्थितियां यह भी है कि उन तक पांच रुपये नकदी भी नहीं पहुंचती और चार चार बच्चे सामने भूख से बिलबिलाते हैं। लगातार आठ फीसदी की विकास दर प्राप्त करने वाले देश में 65 फीसदी लोग खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में यदि जीने वाले हैं, देश की सचमुच कोई तरक्की नहीं हुई है। भूख से लड़ते हुए लोग विकास में कितना योगदान कर पाएंगे, यह सवाल तब जब सरकार यह दावा सही हो कि खाद्य सुरक्षा के दायरे में 65 फीसदी देशवासी आने वाले हैं।

मजबूरी के नाम पर
विदेशियों का शिकंजा बढ़ाती सरकार

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार उपभोक्ता वस्तुओं, टेलीकॉम, पावर प्लांट और अन्य परियोजना वस्तुओं (खासतौर पर चीन से) के आयातों पर पाबंदी लगाएं। सोना–चांदी के आयातों पर प्रभावी नियंत्रण लगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों पर तीन साल का लॉक–इन पीरियड का प्रावधान लागू किया जाए और विदेशी कंपनियों द्वारा अनधिकृत रूप से किए जा रहे विदेशी मुद्रा अंतरणों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। यदि सरकार ने ये कदम जल्दी नहीं उठाए तो देश भयंकर विदेशी मुद्रा संकट में फंस सकता है।

गत कुछ माह से सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के नाम पर टेलीकॉम, रक्षा, बीमा समेत कई क्षेत्रों में एफडीआई को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटी थी। सरकार के बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी इन प्रयासों का भारी विरोध हो रहा था। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने टेलीकॉम में विदेशी निवेश की सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया था। गृह मंत्रालय का कहना है कि टेलीकॉम, रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक उड्यन इत्यादि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एक सीमा से आगे बढ़कर विदेशियों, खासतौर

पर चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, साऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों को अनुमति देने से देश को सुरक्षा संकट पैदा

■ स्वदेशी संवाद

हो सकता है। इसी तर्ज पर रक्षा मंत्रालय ने भी इन प्रयासों का खासा विरोध किया था और यह कहा था कि इस नीति से देश की अभेद्यता खंडित होगी।

गृह मंत्रालय ने जाहिरतौर पर मीडिया को यह कहा भी था कि टेलीकॉम कमीशन द्वारा इन तमाम क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को स्वचालित मार्ग द्वारा 49 प्रतिशत की अनुमति देने की सिफारिश का गृह मंत्रालय ने पुरजोर विरोध किया है। और उन्होंने इस बाबत एक सख्त पत्र भी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को लिखा है।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा 16 जुलाई 2013 को 13 क्षेत्रों में एफडीआई यानि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सीमाओं को आगे बढ़ा दिया गया।

13 क्षेत्रों में बढ़ेगा विदेशियों का शिकंजा

गौरतलब है कि अब टेलीकॉम में 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दे दी गई है। अति आधुनिक रक्षा उपकरणों के संदर्भ में भी एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया है। बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति लेना जरूरी होगा। तमाम विरोधों के बावजूद सरकार द्वारा एफडीआई सीमा को बढ़ाना इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा कि इससे देश प्रगति करेगा, बल्कि एफडीआई को इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि देश के सामने जो देनदारी का संकट खड़ा है, उससे निपटा जा सके। यानि इस एफडीआई की नीति का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि इससे विदेशी निवेशक देश में धन लाने के लिए आकर्षित होंगे और हम विदेशी भुगतान के घाटे को उससे पाट सकेंगे ताकि गिरते रूपए को थामा जा सके। सरकार द्वारा एफडीआई के आधार पर अपने पूर्व के विकास के नारों को नहीं दोहराया जा रहा, कहीं भी यह

नहीं कहा जा रहा कि देश में विकास को बढ़ाने के लिए एफडीआई जरूरी है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि इससे किसी तरह से हम रूपए पर आए वर्तमान संकट से उबर पाएंगे।

रूपए की कमजोरी से बेबस अर्थव्यवस्था

रूपया अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर 61.21 रूपए प्रति डालर पर पहुंच चुका है। ऐसे सब लोग जो रूपए की गिरावट को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् कहते रहे हैं कि गिरते रूपए से घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार देश की अर्थव्यवस्था में उठाव लाने हेतु भरपूर प्रयास कर रही है। उधर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रघु राजन कह रहे थे कि डालर के मुकाबले दूसरी कैरेंसियां भी कमजोर हो रही हैं इसलिए केवल भारत की चिंता का यह विषय नहीं है।

रूपए में आए इस भारी कमजोरी के कारण आम आदमी, सरकार और अर्थशास्त्री सकते में है। पहले से ही भारी मुद्रा स्फीति की मार झेल रही अर्थव्यवस्था अब रूपए में कमजोरी के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त दंश से त्रस्त है। हमारे तेल, कच्चे माल, सोना–चांदी, मशीनरी इत्यादि के आयात कुछ इस किस्म के हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद घटते नहीं हैं। दूसरी ओर हमारे निर्यात भी अवमूल्यन के कारण बढ़ते नहीं हैं। ऐसे में निकट भविष्य में चालू खाते पर घाटे की स्थिति और बदतर हो सकती है। इन सबके कारण देश पर विदेशी कर्ज और ज्यादा बढ़ने का संकट आ सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई माह के अपने मासिक बुलेटिन में कहा था कि देश में बेबसी के सूचकांक लगातार बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बेबसी (वलन्रेबिल्टि) के कई सूचक होते हैं, एक कुल विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात; दूसरा, कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋणों (एक साल से कम वाले ऋण) का अनुपात; तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार और कुल विदेशी ऋण का अनुपात और विदेशी मुद्रा भंडार और अल्पकालिक ऋण का अनुपात। दुर्भाग्य कहें या नीतिगत कुप्रबंधन यह सभी सूचक बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेबसी की ओर तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

गौरतलब है कि अब टेलीकॉम में 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दे दी गई है। अति आधुनिक रक्षा उपकरणों के संदर्भ में भी एफडीआई की सीमा को बढ़ा दिया गया है। बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति लेना जरूरी होगा।

रूपए में आए इस भारी कमजोरी के कारण आम आदमी, सरकार और अर्थशास्त्री सकते में है। पहले से ही भारी मुद्रा स्फीति की मार झेल रही अर्थव्यवस्था अब रूपए में कमजोरी के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त दंश से त्रस्त है। हमारे तेल, कच्चे माल, सोना–चांदी, मशीनरी इत्यादि के आयात कुछ इस किस्म के हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद घटते नहीं हैं।

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से यह सभी सूचक भारत की मजबूती दर्शा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इनमें बिगाड़ आना शुरू हुआ। यदि कुल विदेशी ऋण और जीडीपी का अनुपात देखें तो 2005–06 में विदेशी ऋण कुल जीडीपी का मात्र 17.2 प्रतिशत ही था। जबकि अब यह बढ़कर मार्च 2012 में 19.7 प्रतिशत और दिसम्बर 2012 में 20.6 प्रतिशत पहुंच गया और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां कुल विदेशी ऋणों में अल्पकालिक ऋणों का अनुपात 2006 में 14.2 प्रतिशत था, वह दिसम्बर 2012 तक बढ़कर 24. 4 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त अल्पकालिक तौर पर लिए गए नए ऋणों का अनुपात तो बढ़कर 44.1 प्रतिशत हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2012 में कुल ऋणों का 85 प्रतिशत से अधिक हुआ करते थे, जो घटकर अब 78.6 प्रतिशत ही रह गए हैं। अल्पकालिक ऋणों के अनुपात के रूप में तो यह और भी कम रह गए हैं। वर्ष 2008 में देश के पास इतनी विदेशी मुद्रा हुआ करती थी, जिससे हम तीन साल तक लगातार आयात कर सकते थे। लेकिन अब विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

विदेशी निवेश नहीं है संकट की दवा

संकट की दवा खोजने के लिए जरूरी है की संकट का कारण स्पष्ट हो। मुख्य प्रश्न यह है कि इतने कम समय में देश की यह दुर्दशा कैसे हो गई? वित्तमंत्री अपना पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि कच्चे तेल, कोयले और सोन–चांदी के आयातों के बढ़ने के चलते ऐसा हुआ है। लेकिन

इससे वित्तमंत्री या सरकार अपनी गलतीयों को छुपा नहीं सकती। यदि पेट्रोलियम पदार्थों की बात की जाए, तो 2011–12 में 155 और 2012–13 में 169 अरब डालर के पेट्रो पदार्थ आयात किए गए, जिसमें मात्र 15 अरब डालर का ही अंतर है। कोयले के आयात से भी कोई बहुत भारी अंतर नहीं पड़ा। यदि किसी एक मद के आयात का असर विदेशी भुगतान पर विशेष पड़ा है, तो वह है सोना और चांदी का आयात। सोना–चांदी के आयात का बढ़ना एक दिन में नहीं हुआ है। पिछले दो सालों से सोना–चांदी का आयात पहले से कई गुणा बढ़ गया है, 2011–12 में यह 60 अरब डालर तक पहुंच गया। सोना–चांदी के आयात बढ़ने की जानकारी सरकार को पहले से ही थी, तो उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? चीन लगातार शत्रुता भाव रखते हुए भारत पर सामरिक दबाव बना रहा है। उसके बावजूद भारत सरकार चीन से आयातों पर रोक लगाना तो दूर, ऐसा लगता है कि उन्हें प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। चीन से व्यापार घाटा 40 अरब डालर तक पहुंच चुका है।

एफ.डी.आई से भी बढ़ रहा भुगतान संकट

सरकार जिस नीति को रामबाण बताकर देश पर लादने की कोशिश कर रही है, वह भी भुगतान संकट का मुख्य कारण है। गौरतलब है कि अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के पांच वर्षों के दौरान देश को कुल 158.8 अरब डॉलर की एफ.डी. आई. प्राप्त हुई, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान 128.2 अरब डॉलर विदेशी कंपनियों के माध्यम से रॉयल्टी, डिविडेंड, ब्याज, वेतन इत्यादि के रूप में विदेशों को अंतरित कर दिए गए। पिछले साल तो एफ.डी.आई. तो मात्र 22.4 अरब डॉलर आयी, लेकिन विदेशों को आय अंतरण 32. 2 अरब डॉलर का हुआ। लेकिन इस एफ. डी.आई. के बदले में देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, कंपनियों, बाजार और संसाधनों पर विदेशी काबिज हो गए। इस दौरान हमने अपने ऊपर भविष्य में अनंतकाल के लिए देनदारी का बोझ ओढ़ लिया। पिछले डेढ़ दशक के विदेशी निवेश का खामियाजा आज देश भुगत रहा है और आज आमंत्रित एफ.डी.आई. का खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी।

आज जरूरत इस बात की है कि सरकार उपभोक्ता वस्तुओं, टेलीकॉम, पावर प्लांट और अन्य परियोजना वस्तुओं (खासतौर पर चीन से) के आयातों पर पाबंदी लगाएं। सोना चांदी के आयातों पर प्रभावी नियंत्रण लगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों पर तीन साल का लॉक–इन पीरियड का प्रावधान लागू किया जाए, विदेशी कंपनियों द्वारा अनधिकृत रूप से किए जा रहे विदेशी मुद्रा अंतरणों पर प्रभावी रोक लगे। यदि सरकार ने ये कदम जल्दी नहीं उठाए तो देश भयंकर विदेशी मुद्रा संकट में फंस सकता है।❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

गरीब की गरीबी के साथ एक बार फिर भद्दा मजाक

सरकार द्वारा घोषित गांवों में 27 रूपए और शहरों में 33 रूपए की परिभाषा देश में किसी के गले नहीं उतर रही। दुनिया भर में गरीबी की मान्य परिभाषा दो डालर के बराबर प्रतिदिन की है, जिसके अनुसार 120 रूपए प्रतिदिन से कम पाने वालो को गरीब ही कहा जायेगा। यदि दो डालर के बजाय सवा डालर प्रति व्यक्ति की आमदनी भी ली जाए, तो भी गरीब की आमदनी कम से कम 75 रूपए प्रतिदिन होनी चाहिए। यानि किसी भी मापदंड के आधार पर सरकार द्वारा घोषित गरीबी की परिभाषा गरीब और गरीबी के मजाक के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

23 जुलाई 2013 को योजना आयोग ने वर्ष 2011–12 के लिए गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया कि अब देश में सिर्फ 22 प्रतिशत लोग ही गरीबी की रेखा से नीचे रहते है। गौरतलब है कि 2004–05 में सरकारी आंकड़ें 37 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे बताते थे। 2009–10 के लिए सरकार ने यह आंकड़ा 30 प्रतिशत बताया था। यानि सरकारी दावा यह है कि 2004–05 से 2011–12 के बीच कुल गरीबों की संख्या 40.5 करोड़ से घटकर अब मात्र 26.9 करोड़ रह गई है, जिसमें से 21.7 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। गरीबी की रेखा को परिभाषित करते हुए सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति की आमदनी गांवों में 27.2 रूपए और शहरों में 33.3 रूपए प्रतिदिन से अधिक है, वह गरीब नहीं है। इन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गांवों में 25.7 प्रतिशत और शहरों में 13.7 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं।

अब यदि गरीबी की इस परिभाषा की तुलना 2009–10 की परिभाषा के साथ करते हैं, तो उस समय योजना आयोग ने यह कहा था कि गांवों में 26 रूपए और शहरों में 32 रूपए प्रतिदिन से अधिक पाने वाले लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। यानि दो सालों में गरीबी की परिभाषा को मात्र एक रूपया प्रतिदिन ही बढ़ाया गया है। गरीबी की इस सरकारी परिभाषा से सरकारी आंकड़ों की प्रासंगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि इस बीच खाद्य पदार्थों की कीमतें ही 17 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में अपनी उपलब्धि दिखाना चाहती है।

जब सरकार ने दो साल पहले वर्ष 2009–10 के गरीबी के आंकड़ें प्रकाशित किए थे, तब भी एक जनहित याचिका की सुनवाई के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देष में व्यापक भुखमरी और गरीबी के मद्देनजर आष्चर्य व्यक्त किया था कि सरकार गरीबी की एक नितांत अव्यवहारिक परिभाषा अपना रही है, जिसके अनुसार वर्ष 2004–05 में मात्र 37 प्रतिषत लोग ही गरीब थे। यह तो गनीमत है कि प्रो. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विषेषज्ञ दल ने गरीबी की एक बेहतर परिभाषा दी, अन्यथा भारत सरकार की पूर्व की परिभाषा के अनुसार तो 2004–05 में मात्र 27.5 प्रतिषत लोग ही गरीब रह गये थे। प्रो. तेंदुलकर की परिभाषा के अनुसार भी वर्ष 2004–05 में षहरी क्षेत्रों में 578.8 रूपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 446.7 रूपये से अधिक पाने वाले गरीबी की परिभाषा में नहीं आते थे।

उस समय जब सर्वोच्च न्यायालय ने योजना आयोग को इस संबंध में षपथ पत्र दाखिल करने को कहा तो भी योजना

आयोग ने वर्ष 2009–10 के लिए गरीबी की परिधि में आने लायक आय को षहरी क्षेत्रों में 32 रूपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 प्रतिदिन ही माना। ऐसे में जब देश में महंगाई के बोझ के तले दबी आम जनता का जीना दूभर हो गया है, सरकार के गरीबी के परिभाषा के संबंध में इस अड़ियल रूख के चलते सरकार की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी थी। जबकि गरीबी की इस परिभाषा के मद्देनजर देष में एक बहस षुरू हो चुकी है कि क्या सरकार गरीबों और गरीबी निवारण के प्रति संवेदनषील है भी कि नहीं, योजना आयोग द्वारा हाल ही में जारी गरीबी के आकड़ों ने तो जैसे पुराने जख्म पर फिर से नमक डाल दिया है।

सरकार द्वारा योजना आयोग के इन आंकड़ों को औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है। योजना आयोग का कहना है कि देश में तेजी से हुई आर्थिक प्रगति और सरकार द्वारा चलाये जा रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम, (जिसमें हर वर्ष न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है), मिड–डे मील योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खर्च के कारण यह गरीबी घटी है। गौरतलब है कि सरकार इन मदों पर खर्चें को भी गरीबों के कल्याणकारी खर्चें में शामिल कर रही है। सरकार का यह भी कहना रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के चलते भी गरीबी का प्रकोप घटा है।

लेकिन यदि हम मामले की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में सरकार द्वारा अभी भी गरीबी की वही गलत परिभाषा अपनाई जा रही है, जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। अभी भी दो सालों में गरीबी की परिभाषा को मात्र रूपया प्रतिदिन बढ़ाने के पीछे योजना आयोग और सरकार कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाई है। ऐसे में 2009–10 से 2011–12 के बीच जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतें ही 17 प्रतिशत बढ़ गई तो गरीबी की रेखा कैसे मात्र एक रूपया ही बढ़ी, यह समझ के परे है। इस पर योजना मंत्री राजीव शुक्ला जब वैज्ञानिक आधार पर इन आंकड़ों को औचित्यपूर्ण नहीं दिखला पाए, तो उन्होंने यह कह कर अपना पलड़ा झाड़ लिया कि ये आंकड़े अंतिम आंकड़ें नहीं है और ये केवल एक विशेषज्ञ दल के अनुमान भर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये। लेकिन नरेगा और गरीबी का संबंध धरातल पर दिखाई नहीं देता और न ही ऐसा दिखाई देता है कि आर्थिक संवृद्धि गरीबी को घटा रही है। उदाहरण के लिए बिहार द्वारा 2004–05 से 2019–10 के कालखंड में 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से आर्थिक संवृद्धि रिकॉर्ड की गई, लेकिन वहां गरीबी नहीं घट पाई। पिछले दो वर्षों में 53.5 प्रतिशत से घट कर गरीबी मात्र 33.7 प्रतिशत ही रह गई जो सरकारी

स्पष्ट है कि परिभाषा बदलते हुए आकड़ों की कारीगरी से तो गरीबी को किसी भी स्तर पर लाया जा सकता है, उसमें सरकार द्वारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गरीबी की रेखा को बदलते हुए अचानक गरीबी को घटाने की कवायद कोई नई बात नही है। इससे पहले भी सर्वप्रथम सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में गरीबी की परिभाषा को बदलते हुए गरीबी के आंकड़ों को कम दर्शाने का प्रयास हुआ था और यह अभी तक चल रहा है।

यह स्पष्ट है कि परिभाषा बदलते हुए आकड़ों की कारीगरी से तो गरीबी को किसी भी स्तर पर लाया जा सकता है, उसमें सरकार द्वारा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गरीबी की रेखा को बदलते हुए अचानक गरीबी को घटाने की कवायद कोई नई बात नही है। इससे पहले भी सर्वप्रथम सरकार द्वारा वर्ष 1993–94 में गरीबी की परिभाषा को बदलते हुए गरीबी के आंकड़ों को कम दर्शाने का प्रयास हुआ था और यह अभी तक चल रहा है।

लेकिन जहां तक सरकार का यह तर्क है कि गरीबी का घटना नरेगा के कारण हुआ है, शायद सही नहीं है। सरकार का कहना है कि चूंकि नरेगा आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा रहें हैं।

सरकार और योजना आयोग हालांकि गरीबी के इन आंकड़ों पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनके तर्कों में विश्वास का अभाव दिखाई दे रहा है। योजना मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि ये आंकड़ें अंतिम नहीं हैं और गरीबी के सही आकलन के लिए सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार का दावा है कि गरीबी के वर्तमान आंकड़े स्वर्गीय प्रो. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाई गई परिभाषा के अनुरूप हैं। प्रो. तेंदुलकर ने वर्ष 2004–05 में गरीबी के आकलन संबंधी पूर्व के सरकारी आंकड़ों को बदलते हुए यह कहा

था कि गरीबी की रेखा सही नहीं है और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को भी शामिल किया जाना चाहिए।

लेकिन गरीबी की परिभाषा में गलती जरूर है क्योंकि सरकार द्वारा घोषित गांवों में 27 रूपए और शहरों में 33 रूपए की परिभाषा देश में किसी के गले नहीं उतर रही। दुनिया भर में गरीबी की मान्य परिभाषा दो डालर के बराबर प्रतिदिन की है, जिसके अनुसार 120 रूपए प्रतिदिन से कम पाने वालो को गरीब ही कहा जायेगा। यदि दो डालर के बजाय सवा डालर प्रति व्यक्ति की आमदनी भी ली जाए, तो भी गरीब की आमदनी कम से कम 75 रूपए प्रतिदिन होनी चाहिए। यानि किसी भी मापदंड के आधार पर सरकार द्वारा घोषित गरीबी की परिभाषा गरीब और गरीबी के मजाक के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।

लेकिन एक विषय जिसपर कोई चर्चा नहीं हो रही, वह है, देश में बढ़ती असमानतायें। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि देश में औसत आमदनी बढ़ी है। वर्ष 2011–12 में देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (चालू कीमतों पर) लगभग 61564 रूपये प्रति वर्ष थी, जिसका मतलब है 169 रूपए प्रतिदिन। लेकिन सरकार द्वारा घोषित गांवों में 27 रूपए और शहरों में 33 रूपए की प्रतिदिन आमदनी, चीख–चीख कर देश में असमनाताओं के तांडव को बयान कर रही है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जिस ग्रोथ (आर्थिक संवृद्धि) का दंभ सरकार भर रही है, वह गरीबी घटाने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं है। ऐसा इसलिये है कि गरीब आदमी की आय में उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही क्योंकि देश में आय की असमानताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी 2005 से 2010 के बीच 5 वर्षों में आय की असमानतायें तेजी से बढ़ी हैं। आय की असमनताओं का सूचक गिनी चरांक 31.11 से बढ़कर 33.9 हो गया है। असमानताओं में यह वृद्धि सभी प्रांतों में दिखाई देती है। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

कृषि संकट को बुलावा

मैं जिस अंधकारमय भविष्य की बात कर रहा हूं, वह दूर की कौड़ी नहीं है। यह हमारे जीवनकाल में ही होने जा रहा है। यह जैव आतंकवाद मानवजाति का दुश्मन है। अब भी वक्त है कि किसान जीएम फसलों के घातक दुष्परिणामों को समझें। सरकार को तो जैसे कृषि, पर्यावरण और किसानों की चिंता ही नहीं है।

■ **देविन्दर शर्मा**

कृषि विशेषज्ञों, एनजीओ और किसानों की आपत्तियों को दरकिनार कर पिछले दिनों सरकार ने नेशनल बायोटेक्नॉलोजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल लोकसभा में पेश कर ही दिया। इस बिल के विरोध में बड़ी संख्या में किसानों, कृषि विशेषज्ञों, समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने जंतर–मंतर पर प्रदर्शन का फैसला किया है।

दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रयोगों व अनुभवों से यह बात पुष्ट हुई है कि जीएम फसलें मानव के साथ–साथ कृषि के लिए भी बेहद नुकसानदायक हैं। जीएम बीज कुछ ऐसी खरपतवार और कीट फैला रहे हैं, जो भारतीय कृषि के लिए बड़े संकट में तब्दील होने जा रहे हैं। कई साल पहले जब भारत ने पीएल–480 के तहत अमेरिका से गेहूं का आयात किया था, तो गेहूं के साथ–साथ कुछ अनजान खतरनाक खरपतवार भी भारत आ गए थे। इनमें से दो कांग्रेस या गाजर घास तथा फुलनू अब तक एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। इन दोनों घातक खरपतवारों को नियंत्रित करना बेहद कठिन है।

फुलनू 1.32 करोड़ हेक्टेयर में फैल चुकी है और इसे उखाड़ने में आने वाला अनुमानित खर्च पांच सौ रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक है। कमोबेश यही हाल कांग्रेस घास का भी है, जो नेपाल के कुल क्षेत्रफल के बराबर के रकमे में फैल चुकी है।

पहले ही खरपतवारों के हमले झेल रहा भारत अब एक नई मुसीबत – महाखरपतवार का सामना कर रहा है।

इस खरपतवार को खत्म करना बहुत मुश्किल है। इस पर रासायनिक छिड़काव भी आसानी से असर नहीं करते। यह खतरनाक खरपतवार अमेरिका, कनाडा जैसे उन 26 देशों में महामारी की तरह फैल रही है, जहां जीएम फसलें उगाई जाती हैं। इन खरपतवारों का किसी दूसरे देश से आयात नहीं होता, बल्कि ये तब पैदा होती हैं, जब जीएम फसलों की जुताई होती है। जहां–जहां जीएम फसलों का व्यावसायीकरण होता है, कीट और खरपतवार न केवल इन फसलों से प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेती हैं, बल्कि जल्द ही शैतान की तरह बेकाबू होने लगती हैं।

दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रयोगों व अनुभवों से यह बात पुष्ट हुई है कि जीएम फसलें मानव के साथ–साथ कृषि के लिए भी बेहद नुकसानदायक हैं। जीएम बीज कुछ ऐसी खरपतवार और कीट फैला रहे हैं, जो भारतीय कृषि के लिए बड़े संकट में तब्दील होने जा रहे हैं। कई साल पहले जब भारत ने पीएल–480 के तहत अमेरिका से गेहूं का आयात किया था, तो गेहूं के साथ–साथ कुछ अनजान खतरनाक खरपतवार भी भारत आ गए थे।

अमेरिका का उदाहरण देखें। दस साल पहले कृषि–व्यापार कंपनी मोनसेंटो ने दावा किया था कि उसकी जीएम फसलों से राउंडअप वीडीसाइड्स खरपतवार नहीं फैलता। लेकिन आज, अमेरिका की कृषि योग्य भूमि का करीब आधा भाग इस भयानक खरपतवार की जद में आ चुका है। 2010 से 2012 की तीन साल की अल्पावधि में ही इन महाखरपतवारों से प्रभावित इलाका 3.26 करोड़ एकड़ से बढ़कर 6.12 करोड़ एकड़ हो चुका है।

अमेरिका के ही जॉर्जिया प्रांत में एक लाख एकड़ से अधिक जमीन पिगवीड महाखरपतवार की गिरफ्त में आ चुकी है। किसान दस गुना खरपतवार नाशक छिड़काव के बाद भी इसे काबू नहीं कर पा रहे हैं। अब मोनसेंटो कंपनी किसानों को अनेक घातक और यहां तक कि 2,4–डी जैसे प्रतिबंधित कीटनाशकों का घोल मिलाकर छिड़काव की सलाह दे रही है। कनाडा में भी दस लाख एकड़ जमीन राउंडअप वीडीसाइड्स की चपेट में आकर बर्बाद हो चुकी है।

अमेरिका के बाद अब भारत के छोटे किसानों की बारी है। महाखरपतवारों का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। इसका नजला भारतीय खेती पर पड़ेगा। जीएम फसलों से भारत की खेती तबाह हो जाएगी।

अमेरिका के बाद अब भारत के छोटे किसानों की बारी है। महाखरपतवारों का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। इसका नजला भारतीय खेती पर पड़ेगा। जीएम फसलों से भारत की खेती तबाह हो जाएगी।

मेरे शब्दों पर ध्यान दें – देश में जल्द ही किसानों की खुदकुशी के आंकड़े और भी तेजी के साथ बढ़ने जा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदार जीएम फसलों को भारत में उतारने को आतुर कुछ कृषि वैज्ञानिकों और सरकार होगी। विषैली भूमि और जहरीले होते व घटते भूजल के कारण आधुनिक कृषि पारिस्थितिक विनाश की ओर बढ़ रही है, जहां लाइलाज खरपतवारों का राज होगा। न केवल खरपतवार बल्कि नए–नए किस्म के कीटों और सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण के लिए और भी घातक, महंगे और खतरनाक रसायनों पर किसानों की निर्भरता हो जाएगी।

जाहिर है, इसके बावजूद जीत खरपतवारों और कीटों की सेना ही होगी और कृषि संकट तेजी से गहराता चला जाएगा। उद्योग जगत के लिए घातक कीट और खरपतवार पूरी दुनिया में मोटे मुनाफे के अवसर पैदा करते हैं। जीएम कंपनियां किसानों को फसलों पर अधिक तेज और घातक रासायनिक छिड़काव करने के लिए कह रहे हैं। ये अकसर कई तेज कीटनाशकों का घालमेल होते हैं। कृषि–व्यापार कंपनियों के लिए इसमें दोहरा लाभ है। अब विश्व की तीन सबसे बड़ी जीएम कंपनियों का 70 प्रतिशत से अधिक वैश्विक बीज बाजार पर कब्जा है। इसके अलावा इनका कीटनाशक बाजार पर भी दबदबा है। हमेशा बढ़ने वाली रासायनिक कीटनाशकों की ब्रिकी निश्चित तौर पर जीडीपी में तो वृद्धि करती है, लेकिन पर्यावरण और कृषि के भविष्य पर इसका जो विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, उसकी चिंता सरकार को नहीं है।

लाखों एकड़ जमीन में जीएम फसल उगाई जा रही हैं और यह जमीन महाकीटों और महाखरपतवारों का अड्डा बन रही है। इस कारण भविष्य में कृषि की दशा बहुत विनाशकारी होने जा रही है। मैं कभी–कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि महाकीट और महाखरपतवार मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। मैं जिस अंधकारमय भविष्य की बात कर रहा हूं, वह दूर की कौड़ी नहीं है। यह हमारे जीवनकाल में ही होने जा रहा है। यह जैव आतंकवाद मानवजाति का दुश्मन है। अब भी वक्त है कि किसान जीएम फसलों के घातक दुष्परिणामों को समझें। सरकार को तो जैसे कृषि, पर्यावरण और किसानों की चिंता ही नहीं है। ❑

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टैण्डर्ड नहीं है। हमारे लिए अलग है, अमरीका के लिए अलग है। अब कृषि की दृष्टि से केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ, अमरीका के किसानों को जो पहले सब्सिडी मिलती थी, उससे चार गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। भारत और विकसनशील देशों को अमरीका कहता है तुम अपने यहां सब्सिडी कम करो और आखिर में सब समाप्त करो। अपने किसानों की वे सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कहा कि सब्सिडी खत्म करे।

– राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी (सर्वसमावेशी स्वदेशी पुस्तक से)

अपने रुपए को आप बचाइए

रोजगार घटे और महंगाई बढ़े, तो फिर अर्थव्यवस्था में दुष्चक्र शुरू हो जाता है। रुपए की लगातार पिटाई से तो यही साफ होता है कि महंगे डीजल और पेट्रोल के चलते महंगाई की रफ्तार पर सरकार रफ्तार से बयान भर देती रहेगी। कुछ ठोस कर पाना उसके बस में दिखाई नहीं पड़ता सबसे बड़ी बात यह है कि राजकोषीय घाटा कम करने के जो उपाय केंद्र सरकार कर सकती थी, वह इस चुनावी साल में होते दिख नहीं रहे हैं।

■ आलोक पुराणिक

रुपया डूब रहा है, लगातार। 31 जुलाई, 2013 को यह एक डॉलर के मुकाबले 61 रुपए के पार चला गया। यह ऐतिहासिक गिरावट है। ऐतिहासिक तो यूं और भी कुछ है अर्थव्यवस्था में। पर सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि अब आम नागरिक को अपनी खाल बचाने का इंतजाम खुद करना है। सरकार, रिजर्व बैंक, स्टॉक बाजार, तमाम निवेश योजनाओं से किसी किस्म की राहत की उम्मीद नहीं है, कम से कम अगले आम चुनावों तक।

रिजर्व बैंक ने 30 जुलाई, 2013 के पॉलिसी रिव्यू में साफ कर दिया है कि वह ब्याज दरों में कटौती के लिए सांकेतिक कदम भी उठाने नहीं जा रहा है। रेपो रेट 7.25 प्रतिशत रखकर और कैश रिजर्व रेशो को चार प्रतिशत पर रखकर, रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि वह अर्थव्यवस्था में महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और किसी भी किस्म से ब्याज दरों में कटौती का संकेत नहीं देना चाहता।

रिजर्व बैंक चाहता तो इन दरों में बदलाव के जरिये संकेत दे सकता था कि ब्याज दरों में कटौती संभव है। ब्याज दरों में कटौती के मसले पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक लगभग आमने–सामने हो चुके हैं। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम चाहते रहे हैं कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की कमी का सिलसिला शुरू करे, ताकि मंदी में पड़े तमाम उद्योग फिर से तेजी का रुख करें, पर रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर

अपनी चिंताओं में इतना सशंकित रहा है कि ब्याज दरों में कमी का कोई संकेत वह देने को तैयार नहीं है। ब्याज दरों में कटौती से महंगाई बढ़ेगी इस चिंता ने कई उद्योगों को चौपट किया है, पर रिजर्व बैंक की चिंताएं अपनी जगह हैं। उसने यह भी साफ किया कि 2013–14 में विकास दर 5.7 प्रतिशत नहीं रहेगी, यह 5.5 प्रतिशत तक रह जाएगी। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लगभग हर सेक्टर से निराशाजनक संकेत हैं।

रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और गिरेगा। उसे बचाना रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के बूते की बात नहीं है। पर आम आदमी को अपना रुपया बचा लेना चाहिए, क्योंकि मंदी में नौकरियां मुश्किल से बचेंगी और खाने–पीने की चीजों की महंगाई बहुत आसानी से बढ़ेगी। सुनवाई कहीं हैं नहीं। सरकार फिलहाल अगर कहीं दिखती है, तो वह घोटालों की खबरों में और चुनाव की तैयारियों में ही दिखती है। सरकार से कुछ होने वाला नहीं है।

रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार पिट रहा है। एक डालर 61 रुपये का हुआ। यह और गिरता है तो इसका मतलब यह कि कच्चे तेल का आयात महंगा होगा। कच्चे तेल का आयात महंगा होने का मतलब यह है कि भारत में डीजल–पेट्रोल के भाव बढ़ते ही रहने हैं। जिसका परिणाम यह होना है कि लगभग हर चीज की महंगाई कुछ दिनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। रिजर्व बैंक के पास आने वाले रिव्यूज में फिर तर्क होगा कि जब महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो ऐसे में ब्याज दरों की कटौती का कोई तर्क नहीं है। ब्याज दरों में कटौती से महंगाई बढ़ेगी।

रिजर्व बैंक प्रकारांतर से केंद्र सरकार को यह सुझाव देता रहा है कि राजकोषीय घाटा कम किया जाए, उसमें कमी की जाए। राजकोषीय घाटा चुनावी साल में कम किया जाना लगभग असंभव कोटि का काम है। मनरेगा की धांधलियों में व्यर्थ गई रकम का हिसाब मिलना तो दूर, अब खाद्य सुरक्षा योजना भी जल्दी ही बड़ी सी रकम लगभग खर्च करती दिखेगी। चुनावी साल में कोई इस पर ठोस आपत्ति नहीं

करेगा। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण नहीं, ब्याज दरों में कमी नहीं। नतीजा, ऑटो सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर लगभग चीत्कार कर रहे हैं। इन दोनों उद्योगों का कारोबार ब्याज दरों पर टिका है। ईएमआई की रकम छोटी होगी तो कार और मकान का कारोबार बड़ा होगा। ईएमआई कम होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने ब्याज कटौती की संभावनाओं को नकार दिया है। ऑटो बिजनेस ने सरकार से गुहार लगाई कि उसे उत्पाद कर में छूट दी जाए। मंदी के चलते कारोबार ठप हो रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले यूं पिट रहा है कि निकट भविष्य में डॉलर की कमाई के स्रोत खुलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। निर्यात ठप हैं। विदेशी निवेश आ नहीं रहा है। जितना आ रहा है, उस पर भारी कन्फ्यूजन मचा हुआ है।

जेट–इत्तिहाद डील से विदेशी निवेश की उम्मीद बंधी थी, लेकिन वह इतने पचड़ों में पड़ गई कि स्थिति साफ नहीं दिख रही है। वालमार्ट की हाल की गतिविधियों से साफ होता है कि वह रिटेल कारोबार इस देश में बढ़ाने की जल्दी में नहीं है। पहले ही मंजूर शर्त पर पुनर्विचार की बात वालमार्ट कंपनी कर रही है। इससे संकेत मिलते हैं कि जो भारतीय बाजार कुछ सालों पहले तक इतना आकर्षक दिख रहा था, वह तमाम समस्याओं के चलते अब उतना आकर्षक नहीं दिख रहा है। वालमार्ट के निवेश के फंसने से ही साफ होता है कि विदेशी निवेश के जिन प्रस्तावों को सरकार टाप के प्रस्ताव के तौर पर हाईलाइट करने वाली थी, वह खुद अंधेरे में हाथ–पैर मार रहे हैं। कुल मिलाकर साफ यह होता है कि जो निवेश बाहर से प्रस्तावित है, उसमें इतने किंतु–परंतु लगे हैं कि जब तक वह विदेशी निवेश पक्के तौर पर फलीभूत न हो जाएं, तब तक उन्हें लेकर आश्वस्ति नहीं हो सकती।

मनरेगा की धांधलियों में व्यर्थ गई रकम का हिसाब मिलना तो दूर, अब खाद्य सुरक्षा योजना भी जल्दी ही बड़ी सी रकम लगभग खर्च करती दिखेगी। चुनावी साल में कोई इस पर ठोस आपत्ति नहीं करेगा। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण नहीं, ब्याज दरों में कमी नहीं। नतीजा, ऑटो सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर लगभग चीत्कार कर रहे हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों को कुछ समय पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्नता का पुल लगती थी, अब यह उनके लिए पिछड़ेपन की गुफा हो गई है। वे यहां से रकम निकाल रहे हैं, यहां ला नहीं रहे हैं। निवेश ठप यानी परियोजनाएं ठप, यानी रोजगार या तो बढ़ेगा नहीं, या फिर कम होगा। कम होने के उदाहरण सामने आने शुरू हो गए हैं।

मारुति ने अपने अस्थाई कर्मचारियों को विदा करने की प्रक्रिया शुरू की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू की है। नए रोजगार के मौके बन नहीं रहे हैं। आने वाले छह महीने छंटनी के हो सकते हैं। रोजगार अवसरों में कटौती के हो सकते हैं। रोजगार अवसरों में कटौती और निवेश ठप होने की आशंका रिजर्व बैंक को है, तभी हाल के रिव्यू में रिजर्व बैंक ने 2013–14 में विकास दर का अनुमान 5.7 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है।

आशंका यह है कि कहीं यह पांच प्रतिशत से भी कम न चला जाए। कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसी आशंका है कि भारत में 2013–14 में विकास दर पांच प्रतिशत से भी नीचे रहेगी। राजनीतिक नेतृत्व का पूरा जोर जैसे–तैसे समय काटकर वोट बटोरने का है। विकास दर राजनीतिक नेतृत्व की चिंताओं में शामिल नहीं है। रोजगार घटे और महंगाई बढ़े, तो फिर अर्थव्यवस्था में दुष्चक्र शुरू हो जाता है।

रुपए की लगातार पिटाई से तो यही साफ होता है कि महंगे डीजल और पेट्रोल के चलते महंगाई की रफ्तार पर सरकार रफ्तार से बयान भर देती रहेगी। कुछ ठोस कर पाना उसके बस में दिखाई नहीं पड़ता। इस सबके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राजकोषीय घाटा कम करने के जो उपाय केंद्र सरकार कर सकती थी, वह इस चुनावी साल में होते दिख नहीं रहे हैं। उल्टे चुनावी साल में तो मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने का चलन है, उनकी उत्पादकता की चिंता किए हुए बगैर। पूरी स्थिति से पता यह लगता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है और गिरेगा। उसे बचाना रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के बूते की बात नहीं है। पर आम आदमी को अपना रुपया बचा लेना चाहिए, क्योंकि मंदी में नौकरियां मुश्किल से बचेंगी और खाने–पीने की चीजों की महंगाई बहुत आसानी से बढ़ेगी। सुनवाई कहीं हैं नहीं। सरकार फिलहाल अगर कहीं दिखती है, तो वह घोटालों की खबरों में और चुनाव की तैयारियों में ही दिखती है। सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बयानों और आश्वासनों से हालात सुधरने होते, तो वे अब तक दस–बारह बार सुधर गए होते। ❑

बहस

मिड डे मील - बन रही है मौत की खुराक

16 जुलाई 2013 मंगलवार को बिहार के सारण जिले के धर्मासति गंडासन गांव के प्राइमरी स्कूल में विषाक्त मिड डे मील बच्चों को परोस दिया गया जिससे 23 बच्चे कालकलवित हो गये बाद में पुलिस जांच से पता चला कि भोजन में कीटनाशक दवा मिली हुई थी। स्कूल की प्रधानाचार्या को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि यह मिलावट जानबूझ कर की गई तो क्या यह क्रुरता व निर्दयता की हद नहीं थी? क्या ऐसी राजनीतिक साजिश करने के उद्देश्य से नीतिश सरकार को अपदस्थ व बदनाम करने की कोशिश थी?

■ **डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल**

बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने मिड डे मील योजना शुरु की। बच्चों को स्कूल में जाकर शिक्षा की जिज्ञासा शांत करने की अपेक्षा पेट की भूख शांत करना अधिक जरुरी होता है। जब वे काम नहीं करेगें तथा उनके मां व बाप तडके ही रोजगार की तलाश नहीं करेगें तो उनके यहां चूल्हा नहीं जलेगा तथा उन्हें भूखा ही रह जाना पड़ेगा। भारत में 27 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला गरीब व 28 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला गरीब नहीं होता है और ऐसे लोगों की जनसंख्या भी 30 करोड़ के आसपास है।

मिड डे मील योजना की नीति, लागू करने की स्वच्छ नीयत, बच्चों को खाना परोसते समय सेवा भाव की सुखद अनुभूति आवश्यक है परन्तु इन भावनाओं को, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, दंबगता, अखड़पन, वोटों की जातिगत राजनीति, व भोजन के प्रति लापरवाही निगल रही है। मिड डे मील की पवित्र नीति में दंबग लोग पैसा काट कर अपना घर भरना चाहते है। उनका कोई विरोध भला गरीब व भूखे लोग कैसे कर सकते है?

केन्द्र सरकार सर्वशिक्षा अभियान चलाना चाहती है जिसमें यही भूख सबसे ज्यादा अडचन बनीं हुई है तथा निरक्षता का प्रतिशत भी 20 के आंकड़े को पार करता रहता है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह मिड डे मील योजना दी जिसने इस योजना को पंचायतों के प्रधानों, नगरपालिका के अध्यक्षों, सांसदों व विधायकों को यह कहते हुए सौंप दी कि वे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है और वे मिड डे मील का बहुत अच्छा प्रबंध कर सकते है।

मिड डे मील योजना में स्कूल में खाना तैयार करके बच्चों को स्कूल के मध्यावकाश में दिया जाता है जिससे बच्चे घर से भोजन न लेकर आयें। इस मिड डे मील योजना की नीति, लागू करने की स्वच्छ नीयत, बच्चों को खाना परोसते समय सेवा भाव की सुखद अनुभूति आवश्यक है परन्तु इन भावनाओं को, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, दंबगता, अखड़पन, वोटों की जातिगत राजनीति, व भोजन के प्रति लापरवाही निगल रही है। मिड डे मील की पवित्र नीति में दंबग लोग पैसा काट कर अपना घर भरना चाहते है। उनका कोई विरोध भला गरीब व भूखे लोग कैसे कर सकते है? समुंद्र में रहना है तो भला मगरमच्छ से कौन बैर मोल ले। कोई अगर हिम्मत करके भोजन की गुणवत्ता को लेकर विरोध करता भी है तो

अखड़पन से उसको दबा दिया जाता है।

16 जुलाई 2013 मंगलवार को बिहार के सारण जिले के धर्मासति गंडासन गांव के प्राइमरी स्कूल में विषाक्त मिड डे मील बच्चों को परोस दिया गया जिससे 23 बच्चे कालकलवित हो गये बाद में पुलिस जांच से पता चला कि भोजन में कीटनाशक दवा मिली हुई थी। स्कूल की प्रधानाचार्या को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि यह मिलावट जानबूझ कर की गई तो क्या यह क्रुरता व निर्दयता की हद नहीं थी?

क्या ऐसी राजनीतिक साजिश करने के उद्देश्य से नीतिश सरकार को अपदस्थ व बदनाम करने की कोशिश थी? जिस साजिश में बच्चों के जीवन के साथ खेला गया। बिहार में ही इसी तरह मधुबनी जिले में नवतोलिया मिडिल स्कूल में भोजन करने के बाद 50 बच्चे बीमार हो गये। लगातार हुई दोनों घटनाओं से मिड डे मील को लेकर भय का माहौल बन गया। इसके बाद लगभग 2,200 स्कूलों में मिड डे मील का वितरण रुकवा दिया गया। राजनीतिक दलों ने छपरा सहित प्रदेश के कई शहरों में धरना, प्रदर्शन, हिंसा, व आगजनी करके अपना विरोध प्रदर्शन किया।

वर्ष 1975 के आसपास चैने में इस प्रकार की योजना शुरु की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज ने राज्य स्तर पर मिड डे मील योजना को सातवें दशक में शुरु की। उसके बाद गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, ओडिसा में यह योजना शुरु की गई। वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया तथा वर्ष 2005 में सरकार ने इस योजना को सार्वभौमिक कर दिया। इस योजना में देश में 12 करोड बच्चों को दोपहर में 10 लाख प्राथमिक स्कूलों में भोजन दिया जाता है। यह विश्व का बहुत ही महत्वाकांक्षी भोजन कार्यक्रम बन गया है।

अपनी यात्रा के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज ने एक दिन कुछ बच्चों को दोपहर में गाय चराते देखा तो कामराज उनके पास गये और पूछा कि तुम्हें तो इस समय स्कूल में पढना चाहिए था और तुम यहां गाय चराते फिर रहे हो। एक बच्चे ने साहस करते हुए कामराज से कहा कि यदि मैं स्कूल जांऊगा तो क्या मुझे भोजन आप लाकर देंगे। मेरा पेट भरा होगा तभी तो मैं कुछ सीख पांऊगा। बालक का तीर निशाने पर लगा और कामराज को बच्चे की बात का तीर चुभ गया। स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जाने लगा। इस योजना के पीछे मकसद यही था कि देश के 42.5 प्रतिशत बालक जिनकी आयु पांच वर्ष से कम है, वे कुपोषण के शिकार है, उन्हें पोष्टिक भोजन मिल जाये। बच्चों को भुखमरी, गरीबी व अशिक्षा से बचाने के लिए यह योजना लागू की गई।

स्कूलों में नामांकन बढे, साथ मिल बैठ कर समाज के सभी तबके के बालक एक साथ प्रतिदिन भोजन (सहभोज) करेंगे तो सामाजिक पूर्वाग्रहों को दरकिनार करने में आसानी होगी और बच्चों में शिक्षा पढ़ते–पढ़ते आपसी मित्रभाव बढ़ सकेगा।

इस योजना में स्वच्छता सबसे बड़ी कठिनाई थी। विभिन्न राज्यों दिल्ली, गोवा, उत्तरप्रदेश इत्यादि से स्कूल में दूषित खाने की वजह से बच्चे बीमार पड़ने की कई घटनाएं हुई। स्कूल की रसोई के लिए निश्चित मानकों पर ध्यान नहीं दिया गया। भोजन पकाने की सुविधा का अभाव था परन्तु धीरे धीरे भोजन पकाने के लिए रसोई व रसोईयों की माकूल व्यवस्था की जाने लगी। 2004 में तमिलनाडु में 80 से अधिक बालकों की मौत स्कूल की रसोई में आग लगने से हो गई थी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के.कामराज ने एक दिन कुछ बच्चों को दोपहर में गाय चराते देखा तो कामराज उनके पास गये और पूछा कि तुम्हें तो इस समय स्कूल में पढना चाहिए था और तुम यहां गाय चराते फिर रहे हो। एक बच्चे ने साहस करते हुए कामराज से कहा कि यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या मुझे भोजन आप लाकर देंगे। मेरा पेट भरा होगा तभी तो मैं कुछ सीख पाऊंगा। बालक का तीर निशाने पर लगा और कामराज को बच्चे की बात का तीर चुभ गया। स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जाने लगा।

वर्ष 1975 के आसपास चैने में इस प्रकार की योजना शुरु की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. कामराज ने राज्य स्तर पर मिड डे मील योजना को सातवें दशक में शुरु की। उसके बाद गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, ओडिसा में यह योजना शुरु की गई। वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया तथा वर्ष 2005 में सरकार ने इस योजना को सार्वभौमिक कर दिया।

मिड डे मील योजना के लिए वर्ष 2010 में योजना आयोग ने एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया जिसमें बिहार के 70 प्रतिशत बच्चों ने भोजन को लेकर नाखुशी व्यक्त की तथा 10 प्रतिशत बच्चे भोजन की पर्याप्तता को लेकर सवाल खडे कर रहे थे। तीन चौथाई स्कूलों ने खाना पकाने के लिए बर्तनों के अभाव की शिकायत की। परन्तु मिड डे मील योजना के लागू होने के बाद बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में स्कूलों में सबसे अधिक बच्चों के नामांकन हुए। देश के विभिन्न राज्यों में इस सामाजिक योजना का प्रदर्शन का स्तर अलग अलग रहा है।

गुजरात व तमिलनाडु में मिड डे मील योजना बहुत सफल रही है। जबकि बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में इस योजना का प्रदर्शन औसत स्तर का ही रहा है। बिहार में 65,977 किचन कम स्टोर स्वीकृत है परन्तु अभी तक 44,159 ही बन सके है। मिड डे मील के दिशा–निर्देश है कि भोजन को सबसे पहले स्कूल के एक शिक्षक सहित दो–तीन लोग स्वयं जांच करें। बार बार उबाले हुए तेल का प्रयोग नहीं हेागा। सुरक्षा व सफाई का ध्यान जरुरी है। रसोई न होने की स्थिति में बाहर से खाना बन कर आ सकता है। परन्तु सबसे अच्छा है कि भोजन स्कूल में ही बनें।

बिहार के सारण जिले में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के लिए संबंधित लोग जिम्मेदार है। लापरवाही उच्च स्तर की थी। जो भोजन बच्चों को पोषण देता उससे ही उनकी मौत हो गई। यह घटना सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ हो रहे उपेक्षित व्यवहार के साथ साथ सरकारी तंत्र की घोर संवेदनहीनता को भी बयान करती हैं इस घटना में भोजन तैयार करने में लापरवाही तो है ही वहीं बीमार पडे बच्चों के ईलाज के दौरान घोर लापरवाही दिखाई दी।

यह माना जाता है कि बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता की कहीं कोई जांच नहीं होती है। मधुबनी में भी ऐसी ही घटना हुई। इतनी बडी क्षति होने के बाद भी बिहार में भविष्य में स्कूलों में क्या कोई ऐसी ठोस व्यवस्था बन सकेगी जिसमें भविष्य में स्कूली बच्चों के पोषण के नाम पर उनके जीवन से कोई खिलवाड न हो। घटना से संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ साधने का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से क्या 23 बच्चे जीवित हो उठेगें अथवा यह गारंटी हो जायेगी कि भविष्य में अब कोई बच्चा मिड डे मील को खाने से नहीं मरेगा। घटना की गहन अपराधिक जांच की जानी चाहिए।

वर्तमान में राजनेता उल्टा सीधा बोल कर टी.वी. पर छाने की जुगत में रहते है। राजनीतिक साजिश के तहत यदि बच्चों के जीवन को निशाना बनाया जा रहा है तो देश में इससे गिरी हुई और कौन सी बात होगी।

इस तरह की घटनाएं देश भर में समय समय पर आती रहती है। परन्तु राज्यों व केन्द्र सरकार ने अभी भोजन की गुणवत्ता को लेकर सजगता का कोई परिचय नहीं दिया है। मिड डे मील उपलब्ध कराने में लापरवाही, घपले, घोटाले भी बडी मात्रा में किये जाने लगे है। नीति नियंता इस प्रकार की सामाजिक व जनकल्याणकारी योजनाओं को किस लापरवाही व गैर–जिम्मेदारी से चलाते है जिससे घपले व संवेदनहीनता, भ्रष्टाचार बढते ही जा रहे है।

बिहार के शिक्षा मंत्री पी. के. शाही कहते है कि बिहार में सारण में बच्चेां को जहरीला भोजन दिया गया, यह जांच होनी चाहिए कि क्या यह दुर्भाग्यवश हुआ अथवा ऐसा जानबुझ कर किया गया। घटना पर राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगे है। पी के शाही ने इसको राजनैतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है यदि यह राजनैतिक साजिश है तो इस घिनौनी राजनीति की जितनी भी निन्दा की जाए, कम है। खाना कहीं भी बने, उसमें सावधानी जरुरी है, बर्तनों का साफ होना भी जरुरी है, भोजन बनाने वालों का साफ होना भी जरूरी है, भोजन सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी जरुरी है।

सरकार बच्चों को खाना देकर कल्याणकारी कार्य करती है पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले लोभी लोग भोजन को विषाक्त कर देते है। मधुबनी में भोजन में छिपकली मिली थी जोकि घोर लापरवाही साबित करती है। राजनेता के. सी. त्यागी ने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार को अस्थिर करने के लिए यह साजिश थी यदि यह साजिश है तो घोर निंदनीय है और यदि इसे राजनीति के तहत साजिश बताया जा रहा है तो भी यह घोर निंदनीय है। वर्तमान में राजनेता उल्टा सीधा बोल कर टी.वी. पर छाने की जुगत में रहते है। राजनीतिक साजिश के तहत यदि बच्चों के जीवन को निशाना बनाया जा रहा है तो देश में इससे गिरी हुई और कौन सी बात होगी। बच्चों की लाशों पर राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे तो इस प्रकार के लोकतंत्र को तिलांजलि ही दे देनी चाहिए। ❑

समस्या

राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़

कमरतोड़ महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस चुनाव के मुद्दों का विषयांतर करने में जुटी है। बटला हाउस मुठभेड़ से लेकर इशरत जहां मुठभेड़ के बहाने कांग्रेस तुष्टीकरण की वही पुरानी काठ की हांडी चढ़ा रही है।

■ **बलवीर पुंज**

बटला हाउस मामले में दिल्ली की अदालत ने दोषी करार दिए गए आतंकी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके पहले अदालत ने शहजाद को दोषी करार देते हुए बटला हाउस मुठभेड़ को असली बताया था। सवाल यह है कि पुख्ता सुबूतों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जो फैसला सुनाया है उस पर संदेह करने वालों का आखिर असली उद्देश्य क्या है?

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अभी भी इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच पर अड़े हैं, उस पर कांग्रेस मौन क्यों है? वास्तव में इन सारे सवालों के केंद्र में कांग्रेस की सोची–समझी साजिश है, जो आगामी चुनाव को देखते हुए रची जा रही है। कमरतोड़ महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस चुनाव के मुद्दों का विषयांतर करने में जुटी है।

बटला हाउस मुठभेड़ से लेकर इशरत जहां मुठभेड़ के बहाने कांग्रेस तुष्टीकरण की वही पुरानी काठ की हांडी चढ़ा रही है।

कांग्रेस 'पंथनिरपेक्षता खतरे में है' का नारा लगाकर वस्तुतः अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का कुत्सित प्रयास कर रही है। फिलहाल कांग्रेस की प्रमुख चिंता किसी तरह मुस्लिम वोट बैंक वापस पाना और आगामी चुनाव में जनता का ध्यान अपने कुशासन से हटाकर तथाकथित सांप्रदायिकता की समस्या की ओर मोड़ना है। बटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे। उनकी शहादत को अपमानित करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुठभेड़ की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया।

सितंबर, 2008 में दिल्ली में हुए बम धमाकों में 26 बेकसूर नागरिक मारे गए थे, जबकि 133 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त पांच जिहादियों के बटला हाउस में छिपे होने का सुराग मिलने पर दिल्ली पुलिस के जवान वहां छापेमारी करने गए थे। आतंकियों की ओर से गोलीबारी शुरू किए जाने पर जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए थे। एक ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि दो मौके से फरार हो गए थे। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी आजमगढ़ के निवासी थे। फरार आतंकियों में से एक शहजाद को दो साल बाद

कांग्रेस का सेक्युलरवाद अल्पसंख्यक वर्ग के कट्टरपंथी तत्वों का तुष्टीकरण और भारत की बहुलतावादी सनातनी संस्कृति के विरोध का पर्याय बन गया है। आतंकवाद को किसी जाति या मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत में मजहब विशेष के कट्टरवाद को पुष्ट कर रही है।

आजमगढ़ स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद से आजमगढ़ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सेक्युलर दलों के लिए एक तीर्थ बन गया।

बटला मुठभेड़ से पूर्व अहमदाबाद बम धमाकों के सिलसिले में आजमगढ़ के ही एक मौलाना अबू बशर को गिरफ्तार किया गया था। बशर की गिरफ्तारी के बाद भी उसके घर मातमपुर्सी के लिए सपा–बसपा और कांग्रेस में होड़ लग गई थी। स्वाभाविक है कि जब सत्ताधारी दल राष्ट्रहितों की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करता है तो न केवल सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिरता है, बल्कि राष्ट्रविरोधी शक्तियों को भी ताकत मिलती है।

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में भी मुसलमानों का भयादोहन करने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने आतंकी संगठन 'इंडियन मुजाहिदीन' का बचाव करते हुए कहा कि इसका गठन गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए किया गया। जिस इंडियन मुजाहिदीन को पुख्ता सुबूतों के आधार पर खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान पोषित आईएसआई और लश्करे तैयबा की पैदाइश बता रही हैं, जिस आतंकी संगठन पर 2006 में मुंबई की ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध धमाके, बेंगलूर के क्रिकेट स्टेडियम, पुणे की जर्मन बेकरी, वाराणसी मंदिर और अब बोधगया में हमलों का आरोप है, उसे कांग्रेस कुतकरें के दम पर न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रही है।

सच्चाई यह है कि इंडियन मुजाहिदीन उस 'सिमी' संगठन का नया अवतार है, जिसे सेक्युलरिस्ट मुस्लिम छात्रों का संगठन बताकर उसका बचाव करते रहे हैं। वर्तमान विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे तब वह 'सिमी' की ओर से न्यायालय में वकालत करते थे। आतंकी गतिविधियों का खुलासा होने पर सिमी को प्रतिबंधित किया गया, जो बाद में आईएसआई की मदद से 'इंडियन मुजाहिदीन' के नाम से खड़ा किया गया।

वस्तुतः कांग्रेस का सेक्युलरवाद अल्पसंख्यक वर्ग के कट्टरपंथी तत्वों का तुष्टीकरण और भारत की बहुलतावादी सनातनी संस्कृति के विरोध का पर्याय बन गया है।

आतंकवाद को किसी जाति या मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत में मजहब विशेष के कट्टरवाद को पुष्ट कर रही है। इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर कांग्रेस ने 'हिंदू आतंक व भगवा आतंक' का हौवा खड़ा करने का कुप्रयास किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का मिथ्या आरोप इसी षड्यंत्र का हिस्सा है।

बम धमाकों के सिलसिले में आजमगढ़ के ही एक मौलाना अबू बशर को गिरफ्तार किया गया था। बशर की गिरफ्तारी के बाद भी उसके घर मातमपुर्सी के लिए सपा–बसपा और कांग्रेस में होड़ लग गई थी। स्वाभाविक है कि जब सत्ताधारी दल राष्ट्रहितों की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करता है तो न केवल सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिरता है, बल्कि राष्ट्रविरोधी शक्तियों को भी ताकत मिलती है।

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पार्टी के एक अधिवेशन में संघ की तुलना सिमी से की थी। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद का प्रतीक बताया। संघ पर अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने का प्रशिक्षण देने का आरोप भी लगाया गया है। आश्चर्य नहीं कि मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के लिए भी कांग्रेसी नेताओं ने संघ को दोषी ठहराने की कोशिश की। यह एक तीर से दो शिकार करने का प्रयास था। एक तरफ संघ पर यह मिथ्या आरोप थोप कर असली आतंकियों को बचाना और दूसरा, देशभक्त संगठनों को कमजोर करना।

सवाल उठता है कि क्या आईएसआई और कांग्रेस का एक ही तरह से सोचना क्या संयोगमात्र है? गुजरात आज 2002 के दंगों से उबरकर विकास के जिस सोपान पर खड़ा है, क्या उस खुशहाली में हिंदू–मुसलमानों की समान भागीदारी नहीं है?

स्वयं सच्चर आयोग ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले गुजरात के मुसलमानों की स्थिति बेहतर बताया है। गुजरात में दंगों का इतिहास रहा है, किंतु पिछले दस सालों में वहां एक भी दंगा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में भीषण दंगे होते रहे हैं।

1993–94 के महाराष्ट्र दंगे, मेरठ के निकट मलाना के दंगे, भागलपुर के दंगे कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों के वीभत्स उदाहरण हैं। 1984 का सिख नरसंहार कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय है, किंतु कांग्रेस सियासी लाभ के लिए गुजरात दंगों को जिंदा रख अल्पसंख्यकों को भड़काए रखना चाहती है। क्या इस तरह की अलगाववाद की राजनीति, जो देश में आतंक को प्रश्रय दे, से मुसलमानों या देश का भला हो सकता है? क्या राजनीति का यह विकृत रूप देशद्रोह का पर्याय नहीं है? ❑

समाचार परिक्रमा

हर क्षेत्र में बढ़ी एफडीआई की सीमा

अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के नाम पर केन्द्र सरकार ने दर्जनभर क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी है। सरकार रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की मौजूदा सीमा 26 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है। यदि इससे ज्यादा का कोई प्रस्ताव आता है तो उसे कैबिनेट की रक्षा मामलों संबंधी समिति से मंजूरी मिलने के बाद स्वीकार किया जा सकता है। यूपीए–2 सरकार ने ये फैसले अरविंद मायाराम समिति की सिफारिश के आधार पर लिए है। समिति ने 20 क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। यूपीए–2 सरकार ने जनता और राजनीतिक विरोध की परवाह किए बगैर विवादित क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का फैसला किया। ❑

छोटे शहरों में खुलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खुदरा स्टोर

लगता है अब सरकार को विदेशी निवेश के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के नाम पर एफडीआई नियमों को और उदार बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील दी गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी नियमों में ढील देने का निर्णय जुलाई माह में ही ले लिया था। अब मंत्रिमंडल ने भी इन प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकारें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी बहुब्रांड खुदरा कंपनियों को अपने स्टोर्स खोलने की अनुमति दे सकेंगी। बेसिक एवं सेल्यूलर सेवाओं के मामले में एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। ❑

वालमार्ट ने लॉबिंग पर लगाई रोक

वैश्विक खुदरा कंपनी वालमार्ट ने भारत केंद्रित मुद्दों पर अमरीकी सांसदों के बीच लॉबिंग रोक दी है। कंपनी ने भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश पाने के लिए लगातार पांच साल लॉबिंग की थी। यह रोक स्थायी है या अस्थायी इस बारे में कंपनी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। एक तरफ भारत में अमरीकी कंपनी द्वारा भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए लॉबिंग के मामले की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे संसद में पेश भी किया जाना है। दूसरी तरफ वालमार्ट और इसके लिए लॉबिंग करने वाली पंजीकृत फर्मों ने अमरीका के दोनों सदनों में सीनेट और प्रतिनिधि सभा के समक्ष ताजा सूचना रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अनुसार वालमार्ट ने इस वर्ष 30 जून को समाप्त दूसरी तिमाही में लॉबिंग गतिविधियों पर बीस लाख डॉलर यानी 12 करोड़ रुपए खर्च किए है। इस रिपोर्ट में भारतीय लॉबिंग मामला शामिल नहीं है। जाहिर है कि वालमार्ट सहित अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में स्टोर खोलने के लिए सालों से कोशिश कर रही है। ❑

बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना किया मुश्किल

तेजी से नीचे गिरते रुपए की कीमत से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बैंकिंग मेजर क्रेडिट सुइस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 'हमारे रिग्रेशन मॉडल में अगर रुपए में 10 प्रतिशत का ह्रास होता है तो इसे थोक मूल्य मुद्रास्फीति का एक प्रतिशत अंक बढ़ जाता है।' भारत अपनी जरूरत का 75 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और खुदरा तेल की बढ़ती कीमत के साथ जरूरत के सामान में वृद्धि होती जाती है। सरकार को पैट्रोल–डीजल से कुछ कर कम करने चाहिए लेकिन सरकार भी बढ़ती मुद्रास्फीति का रोना रो रही है। आज मध्य वर्ग और उच्च वर्ग सब बढ़ते पैट्रोल–डीजल के रेट से परेशान है। खास कर किसान वर्ग पर भी इसकी मार पड़ी है। देखा जाए तो सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ❑

गरीबी आंकड़ों पर केन्द्र और राज्य सरकारों में भी टकराव

गरीबी रेखा को लेकर राजनीति दलों के बीच बयानबाजी भले ही नई हो लेकिन गरीबों की संख्या को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा है। केन्द्र कहता है देश में सिर्फ 6.5 करोड़ परिवार ही गरीबी रेखा के नीचे है, दूसरी तरफ राज्यों सरकारों का दावा है कि पूरे देश में गरीब परिवार 11.11 करोड़ है। कई समितियां बनाने के बाद भी केन्द्र और राज्यों के बीच गरीबों की संख्या का यह विवाद आज तक सुलझा नहीं है। ❑

रिटेल में विदेशी निवेश के बाद बढ़ेगी बेरोजगारी

संसद की उद्योग संबंधी स्थाई समिति ने आशंका जाहिर की है कि खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों के आने से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों और किसानों को भारी नुकसान होगा। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। समिति ने इसे नियंत्रित करने के लिए खुदरा विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश की है।

समिति के अध्यक्ष और द्रमुक नेता तिरूचि शिवा ने इस संबंध में रिपोर्ट राज्यसभापति हामिद अंसारी को सौंपी। उन्होंने कहा कि खुदरा कारोबारी में विदेशी एजेंसियों को कारोबार की अनुमति दिए जाने से भारतीय उद्योग धंधों को नुकसान होगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग महकमे को इसके नफे–नुकसानी को लेकर गहन अध्ययन कराना चाहिए।

उन्होंने कहा अगर ब्रांड खुदरा कंपनियों पर ठीक तरह से नियमन नहीं होता है तो इसका असर मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों के साथ किसानों और घरेलू मंडियों पर होगा। और मंडियों के समाप्त होने के बाद बड़ी कंपनियां कीमतों में गड़बड़ी करेंगी और हमारे किसान विदेशी कंपनियों के इशारे पर कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। नतीजतन खुदरा कारोबार से जुड़े हमारे लोग आजीविका गंवा देंगे और बेरोजगार हो जाएंगे।

शिवा ने कहा विदेशी कंपनियां कह रही है कि वे लाखों रोजगार सृजित करेंगे। यह सही नहीं है। आज जो काम हजारों लोग करते हैं वे उसे सैकड़ों में करा लेंगे। ❑

दाल से ज्यादा दवा खाने पर खर्च कर रहा है आम आदमी

नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बीते दो दशक में गांव और शहरों में खान–पान तथा जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। रिपोर्ट के अनुसार गांव में एक व्यक्ति हर माह 88 रुपए अपने इलाज पर खर्च करता है, वही शहर में 132 रुपए है जबकि गांव में दाल पर महीने भर का खर्च 40 और शहर में 51 रुपए है। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आम आदमी दाल से ज्यादा दवा खाने पर खर्च कर रहा है। उसके मासिक बजट का अच्छा खासा खर्च इलाज पर हो रहा है। जहां 1993 में गांव का एक व्यक्ति अपने महीनेभर के बजट की 63. 2 प्रतिशत धनराशि खाने–पीने की चीजों पर खर्च करता था जो अब घटकर 48.6 फीसदी रह गई है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 54.7 फीसदी से घटकर 38.5 फीसदी रह गई है। एक तरफ से देखा जाए तो बीते 18 साल में अनाज पर खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 24 से घटकर 12 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 14 से घटकर 7.2 प्रतिशत हो गया है। अब लोग अनाज की बजाय दूसरी वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे है।

किराया भाडा भी कर रहा है जेब ढीली। शहरी क्षेत्रों में 2004–05 से 2011–12 के बीच सबसे ज्यादा एक प्रतिशत वृद्धि भाड़े में हुई है। पहले एक शहरी व्यक्ति महीने के बजट का 6.5 प्रतिशत भाड़े पर खर्च होता था वहीं अब बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 3.8 से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया है। ❑

भारत में बढ़े साइबर हमले

इंटरनेट सर्फिंग में भारतीय महफूज महसूस नहीं करते है। भारत में अब इंटरनेट यूजर्स लगातार हमले का शिकार हो रहे हैं। रूस की साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर्स्की ने एक सर्वे के अनुसार यह बात कही। सर्वे के अनुसार वेब सर्फिंग में भारत 15वां सबसे खतरनाक देश है, जहां वायरस का हमला लगातार बढ़ रहा है।

इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की साइबर सिक्योरिटी की रिपोर्ट भी भारत में इंटरनेट सर्फिंग को खतरनाक मानती है। इसमें कहा गया है कि एशिया पैसिफक में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां से सबसे अधिक स्पैम (ईमेल के जरिए आने वाला वायरस) जनरेशन होता है।

भारत में स्पैम जनरेशन के 35 प्रतिशत और फिशिंग के 11 प्रतिशत मामले होते हैं। रिपोर्ट में सीईआरटी के हवाले से बताया गया है कि भारत में करीब 788 कंप्यूटर प्रतिदिन बूट इंफेक्शन के शिकार होते हैं। भारत में साठ लाख से अधिक कंप्यूटर बूट नेटवर्क के शिकार है। यहां के साइबर कानून भी हमलों से प्रभावशाली तरीके से निपटने में सक्षम नहीं हो रहा है। साइबर मामलों के जानकारों के अनुसार भारत मे साइबर हमलों को अकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब तक भारतीय इंटरनेट यूजर्स पर भी इस दौरान करीब दो करोड़ हमले हुए है। अगर कंप्यूटर संक्रमण की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण यूएसबी ड्राइव्स, सीडी और डीवीडी का इस्तेमाल है। अप्रैल से जून के दौरान भारत के कुल 49.6 फीसदी लोगों ने माना कि उनके ऊपर स्थानीय वायरस का हमला हुआ था। ❑

34 रुपए खर्च करने वाला गरीब नहीं

दिन प्रति दिन बढ़ती महंगाई ने आज भले ही आम आदमी की कमर तोड़ दी हो लेकिन सरकार गरीबी रेखा को बढ़ाने को तैयार नहीं है। योजना आयोग की रिपोर्ट तो यही कहती है। 23 जुलाई को योजना आयोग ने नई गरीबी रेखा जारी की है जिसके अनुसार देश में सिर्फ उसी व्यक्ति को गरीब माना जाएगा जिसका गांव में 816 महीने का खर्च और शहर में 1,000 रुपए से कम होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गांव में 28 रुपए तथा शहर में 34 रुपए रोजाना खर्च करने वाला व्यक्ति बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा।

योजना आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को छिपाने के नाम पर आने वाले चुनाव में अपनी छवि साफ करने के लिए इस प्रकार के बेतुकी फरमान जारी कर रही है। यूपीए–2 सरकार के इस फैसले के बाद ही देश में एक ही झटके में 13.78 करोड़ गरीब घट गए हैं। वर्ष 2009–10 में जहां गरीबों की संख्या 40.7 करोड़ थी लेकिन नई गरीबी रेखा के बाद 2011–12 में यह घटकर 26.9 करोड़ रह गई है। योजना आयोग ने नई गरीबी रेखा उसी तेंदुलकर फार्मूले से तय की है जिसने उसने मार्च 2012 में चौतरफा विरोध के चलते तिलांजलि दे दी थी। इसके बाद सरकार ने गरीबी की परिभाषा पुनः तय करने को रंगराजन समिति बनाई थी जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। योजना आयोग की रिपोर्ट से तो ऐसा ही लगता है जैसे सरकार देश से गरीबी हटाने की बजाए गरीबों को मिटा देना चाहती है। ❑

गांवों में 32 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे

योजना आयोग भले ही देश में गरीबी कम होने का दावा कर रहा है लेकिन हकीकत में आज गांवों की 32 फीसदी आबादी बमुश्किल से अपना गुजारा कर पाती है। इन परिवारों की आय इतनी कम है कि वे रोजमर्रा की जरूरी चीजों को जुटा भी नहीं पाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामाजिक–आर्थिक पैनल (एसईसी) के एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। योजना आयोग के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में 21.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है।

आयोग के मुताबिक 2004–05 से 2011–2012 के बीच गरीबी में 15 फीसदी की कमी आई है और करीब 13.7 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं।

एसईसी की अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ग्रामीण इलाकों में 24. 8 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे है।

अध्ययन में पांच मानदंडों को गरीबी का आकलन करने के लिए आधार बनाया गया। एक – बिना छत के घर व जनजातीय पृष्ठ भूमि। जिनके पास मोबाइल, तीन कमरों का पक्का घर है, उन्हें गरीबी की सूची से बाहर कर दिया है। जबकि अत्यंत गरीब का पता लगाने के लिए सात मानकों को आधार बनाया गया। जैसे ऐसा परिवार जिसकी मुखिया महिला है और कमाने वालों में कोई भी पुरुष शामिल नहीं है, उसे वंचित वर्ग में रखा गया है। ❑

भारत से सीखेगा अमेरिका आतंकवाद से लड़ना

एक तरफ देश की साख गिरती जा रही है। दूसरी तरफ हमारी सेना का गौरव दिन–प्रति–दिन बढ़ता जा रहा है जो देश के लिए गर्व की बात है। अब अमरीका भी भारतीय जवानों से सीखना चाहता है। भारतीय सेना के सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों से प्रभावित अमेरिकी सेना प्रमुख ने दोनों देशों की सेना के बीच साझा प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है। दोनों देशों की सेना के बीच सीखने की बहुत कुछ संभावनाओं का उल्लेख करते हुए अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल ने साझा प्रशिक्षण की बात कही है ताकि जटिल परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियान के भारत के अनुभव से लाभ हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा, हम पर्वतीय परिस्थिति में साझा प्रशिक्षण करना पसंद करेंगे क्योंकि बीते कई वर्षों में भारतीय सेना ने जो सीखा है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में हमने जो सीखा है, हम उसे साझा करना पसंद करेंगे। हम अनुभवों को साझा करना और यह देखना चाहेंगे कि हम एक–दूसरे से कैसे सीख सकते हैं तथा भविष्य में प्रत्यक्ष तौर पर इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ❑

फिर पाक की नापाक हरकत

एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू–कश्मीर के पुंछ सेक्टर के अंदर घुसकर भारतीय जवानों पर हमला किया। ये शहीद जवान 21 बिहार यूनिट के जवान थे। इस घटना पर संसद से लेकर सड़क तक गुस्सा फूट पड़ा। केन्द्र सरकार फिर उचित कार्रवाई का आश्वसान देती है, ऐसा कब तक चलेगा इस पर मौन रहती है। ❑

अब आपके मोबाइल फोन पर हैकिंग का खतरा

आज जो हम सिम कार्ड अपने फोन में इस्तेमाल कर रहे है। वह सत्तर के दशक की तकनीक के इस्तेमाल से सिम कार्ड बना है। जिसमें वजह से दुनिया में करोड़ों मोबाइल फोनों पर हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है। जर्मनी के एक मोबाइल सुरक्षा विशेषज्ञ ने अपने शोध में यह दावा किया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञ कर्स्टन नॉल का कहना है कि सत्तर के दशक से सिम कार्ड में कोडिंग के लिए डीईएस (डाटा एंक्रिप्शन स्टैंडर्ड) का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीईएस की वजह से कोई भी हैकर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन पर अपना नियंत्रण आसानी से कर सकता है। इसके लिए बस एक एसएमएस के जरिए वायरस भेजक यह काम किया जा सकता है। फोन को हैक करने के बाद हैकर मोबाइल पर हो रही बातों को सुनने के अलावा उससे खरीदारी भी कर सकता है। हालांकि मोबाइल कंपनियों का कहना है कि दुनिया में बहुत कम सिम कार्ड में पुरानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

एंड्रॉयड फोन भी हैकिंग से सुरक्षित नहीं है। ब्ल्यूबॉक्स सिक्योरिटी के मुताबिक एंड्रायड पर आधारित 99 प्रतिशत मोबाइल फोन और टेबलेट्स आसानी से हैक किए जा सकते है। ❑

दागी कौन? अब कोर्ट नहीं संसद तय करेगी

अब दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रही है। सभी पार्टियों के सांसदों ने एक सर्वदलीय बैठक में कोर्ट के फैसलों पर असहमति जताई गई। सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी कि 'दागी नेता' किसे कहा जाएगा, यह फैसला कोर्ट नहीं बल्कि संसद तय करेगी। साथ ही सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून से देश की राजनीतिक पार्टियां बाहर रहेंगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब सरकार को संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश करना होगा। यूं तो सरकार आरटीआई को जनता के हाथ में ताकत देने का बड़ा हथियार बताती है लेकिन खुद इसके दायरे से बाहर रहने में जुटी रही है। विपक्षी दल भी इस प्रस्ताव पर संसद में सरकार को समर्थन देने का भरोसा दे रहा है। ❑

दुनिया की सबसे बढ़िया टैक्सी एम्बेसडर कार

अगर आज के दौर में कहा जाए टैक्सी में सबसे बढ़िया एम्बेसडर कार है तो सुनकर आश्चर्य होगा! लेकिन वैश्विक ऑटोमोटिव कार्यक्रम टॉप गियर ने एम्बेसडर कार को दुनिया की सबसे बढ़िया टैक्सी बताया है। बीबीसी पर प्रसारित एक ऑटो शो में टॉप गियर के कार्यकारी निदेशक रिचर्ड हेमंड ने दुनिया भर की टैक्यिों पर कार्यक्रम कराया, जिसमें एम्बेसडर बाकी सभी कारों को पछाड़ते हुए विजेता के रूप में उभरी। हिन्दुस्तान एम्बेसडर की शुरूआत ब्रिटेन में मोरिस ऑक्सफोर्ड के रूप में हुई थी, लेकिन नाम में बदलाव के साथ यह भारत का सबसे स्थायी वाहन बन गई। सी.के. बिड़ला ग्रुप की कंपनी हिन्दुस्तान मोटर्स ने वर्ष 1948 में एम्सेबडर बनानी शुरू की। ❑

आतंकी हमलों से बचाव करेगी भारतीय किट

एक बार फिर दुनिया को भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मानना पड़ा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किट विकसित की है जो विस्फोटों का तेजी से पता लगाने में काफी मददगार बनेगी। साथ ही इससे संभावित आतंकी हमलों से निपटा जा सकेगा। लेकिन अब यह किट अमेरिका में बनेगी और इसे दुनियाभर में बेचा जाएगा। पहली बार भारत में विकसित प्रौद्योगिकी को अमरीका में इस्तेमाल कर, इसका उत्पादन किया जाएगा। उद्योग जगत के अनुसार यह संभवतः पहली बार है कि रक्षा अनुसंधान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं विपणन अमेरिका में हो। ❑

देर से हुए आर्थिक सुधार का फायदा कम : अजीम प्रेमजी

देश के जाने–माने उद्योगपति और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर केन्द्र सरकार के काम–काम पर उंगली उठाई है। अजीम प्रेमजी ने कहा कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और सरकार के आर्थिक सुधार के प्रयास भी कारगर ढंग से लागू नहीं हुए है। यह पहला मौका नहीं है जब अजीम प्रेम ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। इससे पहले वर्ष 2011 में भी उन्होंने कहा था कि सरकार में फैसला लेने की क्षमता नहीं है जो देश की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने कहा देश का आईटी क्षेत्र कुछ वर्ष पूर्व 30 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा था लेकिन अब यह बेहद मुश्किल लग रहा है। ❑

डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना जारी

अगस्त माह के शुरुआत में वित्तीय बाजार भरभरा गया है। रुपया एक समय अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा तो बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स करीब 450 अंक का गोता लगाकर 19 हजार से नीचे आ गया। साथ ही सोने की मांग न होने से सोने में भी गिरावट का रुख रहा। सेवा क्षेत्र के पिछले चार वर्षो के सबसे खराब दौर में जाने के संकेत मिले हैं। अंतः वित्त मंत्रलय को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि अर्थव्यवस्था की दुर्गति को दूर करने के लिए उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। देश के नीति निर्धारकों के लिए चुनौती बने रुपये में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिख रहे। कारोबार के शुरुआती दौर में डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 61.80 के स्तर पर पहुंच गई। ❑

2014 में भी पैट्रोल-डीजल-सीएनजी जेब पर डालेगी बोझ

वैसे ही जहां जनता महंगाई से त्रस्त है दूसरी तरफ पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ जाती है लेकिन अब सरकार सीएनजी के भी दाम बढ़ने को तैयार है। जो लोग महंगे पेट्रोल–डीजल से निजात पाने के लिए सस्ती सीएनजी का इस्तेमाल वैकल्पिक ईंधन के रूप में कर रहे थे। अब अगले साल अप्रैल 2014 से प्राकृतिक गैस के दाम दोगुना करने के सरकार के फैसले से सीएनजी 8.20 रुपये से 11.72 रुपये किलो तक महंगी हो जाएगी। पेट्रोलियम राज्य मंत्री पानाबाका लक्ष्मी ने यह जानकारी दी है। इससे दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों जहां सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है वहां न सिर्फ कार चलाना महंगा हो जाएगा बल्कि ऑटो, टैक्सी और बस के किराये में भारी इजाफा होगा। कई शहरों में इसकी कीमत लगभग डीजल के बराबर हो सकती है। ❑

किसानों ने बचाई देश की लाज

आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की साख खतरे में है। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले दो कौड़ी का हो गया है। इस विकट परिस्थिति में प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती को किसानों ने सहर्ष स्वीकार किया है। जहां उद्योग, व्यापार और सेवा जैसे क्षेत्र सरकार से खैरात मांग रहे हैं, वहीं किसानों कृषि के बूते देश को बड़ा सहारा दिया है। उन्होंने बढ़ते आयात के बीच कृषि उपजों और उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर देश की नाक ऊंची की है। लेकिन अफसोस आज उनकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है। भले ही निर्यात में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों की चर्चा हो तो रही है, लेकिन दबी जुबान से। कृषि मंत्री शरद पवार ने कृषि उपजों के निर्यात पर किसी तरह की पाबंदी के खिलाफ तो बयान दिया, लेकिन कृषि क्षेत्र से हुए धुआंधार निर्यात के लिए किसानों की तारीफ नहीं की। वर्ष 2012–13 के दौरान देश से कृषि उत्पादों का कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इसके मुकाबले कृषि संबंधी आयात केवल एक लाख करोड़ रुपये का हुआ है। ऐसे में 1.31 लाख करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय हुई है। ❑

कॉल सेन्टर पर मंडराया संकट

पुरानी कहावत है कि दूसरों के भरोसे अपनी दुकान चलाना, काफी दिनों तक नहीं चल सकती। यही बात आज काल सेन्टरों पर लागू हो रही है। वर्तमान समय में अमरीकी संसद में पेश हुए एक विधेयक ने इन दिनों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों की चिंता बढ़ा दी है। यह बिल आउटसोर्सिंग व कॉल सेन्टर की नीतियों को लेकर है। इसमें अमरीकी कंपनियों द्वारा अपना काम भारत सहित अन्य देशों से करवाने पर आपत्ति जताई गई है।

जहां आज सरकार देश में विदेशी निवेश के सपने दिखा रही है ठीक इसी प्रकार आडटसोर्सिंग व कॉल सेन्टर का प्रवेश भारत में आया था। शुरूआत में काफी लोगों को काम मिला परन्तु अब लोगों का काम छिनना जारी हो गया है। आज सबसे बड़ा बीपीओ कारोबार भारत में है जिसमें 83 फीसदी आउटसोर्सिंग कंपनियां है जिसके द्वारा 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब इन पर बेरोजगारी की तलवार लटकी पड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों और उनके द्वारा दिए गए रोजगारों के सहारे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। ❑

विकासशील देशों को विश्व बैंक ने दी सहायता राशि

विष्व बैंक ने 30 जून को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2013 में विकासषील देषों की सहायता के लिए कर्ज, अनुदान, शेयर निवेष और गारंटी के क्षेत्र में 52.6 अरब डॉलर दिए। अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा, हम अभी इस स्थिति में है कि विकासषील देषों की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ❑

लेख

स्वतंत्रता संग्राम में किसानों का योगदान

सन् 1916 में गांधी जी कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात् चम्पारण में किसानों पर नीलहों के अत्याचार की जानकारी लेने चम्पारण पहुंचे। नीलहे अंग्रेज होते थे। वे चम्पारण के गांव–गांव में कोठी बना लिए थे। उन्होंने किसानों के लिए एक बीघा जमीन में से तीन कठ्ठा नील बोना अनिवार्य कर रखा था। महात्मा गांधी ने प्रथम बार यहां सत्याग्रह का प्रयोग किया और वे सफल हुए।

■ उमेश प्रसाद सिंह

महात्मा गांधी ने चम्पारण (बिहार) में इतिहास प्रसिद्ध किसान आन्दोलन का नेतृत्व किया था। जब गांधी जी को अफ्रीका से आए हुए सिर्फ चार वर्ष हुए थे। सन् 1916 में वे कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात् चम्पारण में किसानों पर नीलहों के अत्याचार की जानकारी लेने चम्पारण पहुंचे। नीलहे अंग्रेज होते थे। वे चम्पारण के गांव–गांव में कोठी बना लिए थे। उन्होंने किसानों के लिए एक बीघा जमीन में से तीन कठ्ठा नील बोना अनिवार्य कर रखा था। महात्मा गांधी ने प्रथम बार यहां सत्याग्रह का प्रयोग किया और वे सफल हुए। यहां नीलहों का अत्याचार समाप्त हुआ। उनके इन कार्यों से चम्पारण के किसानों में खुशी की लहर पैदा हो गई और वे मोहनदास करमचन्द गांधी को महात्मा गांधी कहने लगे। बाद में यही नाम प्रसिद्ध हो गया।

उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। क्रांति में असफलता के पश्चात् लोमराज सिंह ने स्थानीय जगीरहा कोठी में नौकरी कर ली। उस समय लोमराज के घर वालों ने अपना मकान बनाने के लिए ईंट का निर्माण कराया था। नीहले कोठी ने कहा "ईंट मुझे दे दो। इन ईंटों से कोठी में नील बनाने के लिए बड़े नाद बनवाने हैं। घर वालों ने ईंट देने से मना कर दिया।

चम्पारण में महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भी यहां के किसान अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। अंग्रेज उन्हें तरह–तरह की यातना और दंडित करते थे।

ईंटों के लिए झगड़ा

1857 की क्रांति में यहां का नेतृत्व एक किसान लोमराज सिंह ने किया। उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। क्रांति में असफलता के पश्चात् लोमराज सिंह ने स्थानीय जगीरहा कोठी में नौकरी कर ली। उस समय लोमराज के घर वालों ने अपना मकान बनाने के लिए ईंट का निर्माण कराया था। नीहले कोठी ने कहा "ईंट मुझे दे दो। इन ईंटों से कोठी मेंनील बनाने के लिए बड़े नाद बनवाने हैं। घर वालों ने ईंट देने से मना कर दिया। तब कोठी से ओदश आया कि बिना अनुमति के आपने ईंट का निर्माण क्यों किया। विवाद गहरा गया। कोठी ने धमकाया 'ईंट उठाकर ले जाएंगे।'

लोमराज ने कहा 'मेरी ईंट ले जाएंगे तो आपकी कोठी का ईंट तोड़कर मैं अपना शौचालय बना लूँगा।' उस समय कोठी की भय से किसी को बोलने की हिम्मत नहीं था। वही लोमराज सिंह जैसा निर्भीक किसान भी था।

सलामी लें साहेब

सन् 1880 कही घटना है। मिर्जापुर की कोठी का मालिक बार्कले था। वह किसानों पर भारी अत्याचार करता था। एक दिन जंगल की ओर हवाखोरी करने निकला था। रास्ते में किसानों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनका नेतृत्व किसान

नेता शीतल राय कर रहे थे। कोचवान उच्च स्वर में बोला 'रास्ता छोड़ दो साहेब बहादुर की सवारी आ रही है।' राह रोकने वालों ने कहा – ''हम साहब से कुछ अर्ज करना चाहते हैं।''

कोचवान ने लगाम खींचकर गाड़ी रोकी। साहेब ने गाड़ी के भीतर से पूछा 'तुम लोग क्या चाहते हो।'

एक ने कहा नील बोने से हमें माफी दी जाए। साहेब अकड़कर बोला 'नहीं मिलेगी माफी। कड़ी सजा दी जाएगी। लगता है किसी ने बहकाया है। कोचवान गाड़ी बढ़ाओ।'

इतने में घोड़े के नजदीक खड़े किसान ने बुग्गी में जुते दोनों घोड़ों के मुँह की लगाम खींच लिया और उन्हें चार–चार लाठी मारी। घोड़े भाग गए।

साहस बटोरकर कोचवान बुग्गी से नीचे उतरा और दो डंडा खाते ही नौ दो ग्यारह हो गया।

'सलामी कबूल करें साहेब बहादुर।' यह कहते हुए किसानों का डंडा दनादन गाड़ी पर गिरने लगा। डंडा का चोट खाते ही साहेब बहादुर कूद कर भागे, किसानों ने पीछा किया। वे तेजी से भागकर कोठी में छुप गए। किसानों ने उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।

हाथ में कोड़ा

सन् 1895 की घटना है। पूर्वी चम्पारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल में बरका गांव है। उस गांव के पास परेवा कोठी थी। यहां के अंग्रेज साहब का नाम तेलहड़ था। वह हाथ में कोड़ा रखता था। उसे देखते ही सभी लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते थे। वह रैयतों को बिना बात के कोड़े से पीटने लगता था। एक दिन उसी गांव के ऋतुराज सिंह अपने बगीचे में बेटे के साथ कृषि कार्य कर रहे थे।

चम्पारण में सबसे बड़े किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के प्रयास से किसान आन्दोलन यहां चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। राजकुमार शुक्ल अत्यंत निर्भीक और साहसी किसान नेता थे। यह घटना सन् 1901 की है। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उनके पिता श्री कोईराला शुक्ल अपने खेत में आलू को खा रहे थे। उसी समय स्थानीय नीलहा एमन का लठैत खेत पर पहुंचा ...

साहेब ने उस किसान के लिए गाली कब दी। बूढ़ा भड़क गया और तेलहड़ साहेब से मलयुद्ध में भीड़ गया। ऋतुराज सिंह के बेटा ने कुदाल से तेहलड़ साहेब की गर्दन काट दी। इस जुर्म में बाप–बेटे को जेल की सजा हुई।

चम्पारण में गांधी जी आए

चम्पारण में सबसे बड़े किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के प्रयास से किसान आन्दोलन यहां चरमोत्कर्ष पर

सन् 1895 की घटना है। पूर्वी चम्पारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल में बरका गांव है। उस गांव के पास परेवा कोठी थी। यहां के अंग्रेज साहब का नाम तेलहड़ था। वह हाथ में कोड़ा रखता था। उसे देखते ही सभी लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते थे। वह रैयतों को बिना बात के कोड़े से पीटने लगता था। एक दिन उसी गांव के ऋतुराज सिंह अपने बगीचे में बेटे के साथ कृषि कार्य कर रहे . . .

पहुंचा। राजकुमार शुक्ल अत्यंत निर्भीक और साहसी किसान नेता थे। यह घटना सन् 1901 की है। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उनके पिता श्री कोईराला शुक्ल अपने खेत में आलू को खा रहे थे। उसी समय स्थानीय नीलहा एमन का लठैत खेत पर पहुंचा और बोला 'आलू में मेरा भी हिस्सा है। नहीं देने पर सौदा महंगा पड़ेगा।'

यह सुनकर युवा राजकुमार की भृकुटी तन गई। उनके पिता को भी बड़ा गुस्सा आया। पूछा 'कैसा हिस्सा?' तुम्हारी जमीन पर बताई रोपा है क्या?' शुक्ला बाप–बेटे का रौद्र रूप देखकर लठैत बड़बड़ाता हुआ लौट गया। उसने बेलवा कोठी के साहेब एमन से शिकायत की। एमन घोड़े पर सवार होकर, शुक्ल के घर पहुंचा और उन लोगों पर काड़े बरसाने लगा। और कहा 'तुम लोग रैयतों को भड़काते हो। मैं तम्हें बर्बाद कर दूँगा। शुक्ल के घर को उन्होंने लूट लिया। अनाज उठा ले गए। उनके कपड़े आग के हवाले कर दिया। युवा राजकुमार शुक्ल को बड़ा गुस्सा आया। उसने जुल्म के प्रतिकार का संकल्प लिया। प्रतिज्ञा स्वरूप अपनी जनेऊ तोड़ ली। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि जब तक अंग्रेज चम्पारण से जाएंगे नहीं तब तक जनेऊ नहीं पहनूँगा। इसी संकल्प ने राजकुमार शुक्ल को चम्पारण का किसान नेता बना दिया। 1916 में वे महात्मा गांधी को लेकर चम्पारण की धरती पर आए और अंग्रेजों का सफाया करके ही दम लिया। इस कार्य में उन्हें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर बाबू आदि का उल्लेखनीय सहयोग मिया। स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने में किसानों का भारी सहयोग रहा है। ❑

रामसेतु का भविष्य...?

नासा और भारतीय सेटेलाइट से लिये गए चित्रों में धनुषकोटि से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है। देश में इसे रामसेतु और विश्व में एडम्स ब्रिज यानी आदमपुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लम्बाई 48 किलोमीटर है। यह ढाँचा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। समुद्र इस बीच 3 फीट से 30 फीट तक गहरा है। अनेक स्थानों पर यह सूखी और कई जगह उथली है। जिससे यहां पर जहाजों का आवागमन संभव नहीं है।

■ पुष्करलाल पुराणिक

पुराणों में

वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब श्रीराम ने सीता को लंकापति रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिये लंकाद्वीप पर चढ़ाई की, तो उस समय श्रीराम की सेना में विद्मान नल–नील नाम के वानरों के सहयोग से पत्थरों का तैरता पुल बनाकर लंका पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। रामायण, महाभारत, रघुवंश, स्कंदपुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्रीराम सेतु का वर्णन किया गया है।

रामसेतु

भारत के दक्षिण–पूर्व में रामेश्वरम् और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की श्रृंखला है। नासा और भारतीय सेटेलाइट से लिये गए चित्रों में धनुषकोटि से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है। देश में इसे रामसेतु और विश्व में एडम्स ब्रिज यानी आदमपुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लम्बाई 48 किलोमीटर है। यह ढाँचा मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। समुद्र इस बीच 3 फीट से 30 फीट तक गहरा है। अनेक स्थानों पर यह सूखी और कई जगह उथली है। जिससे यहां पर जहाजों का आवागमन संभव नहीं है। 1480 ईसवीं के आये चक्रवात के कारण यह टूट गया। इसके पहले तक इस ढाँचे पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था।

रामसेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक, इस विवाद से परे हटकर भू–विशेषज्ञों ने इसे न तोड़ने की हिदायत दी है। उन्होंने आगाह किया है कि एडम ब्रिज को तोड़ना प्राकृतिक तबाही का कारण बन सकता है। सेतु समुद्रम परियोजना विरोधी अंदोलन के तहत एक जुट पर्यावरण वैज्ञानिकों और भू–वेत्ताओं ने कहा है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि टेक्टोनिक यानी आंतरिक हलचलों के लिहाज से काफी कमजोर है। भूकंप से जुड़े खतरों को लेकर भी काफी संवेदनशील है। जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के पूर्व निदेशक के.गोपालकृष्णन ने कहा है कि केंद्र सरकार और सेतु समुद्रम परियोजना प्राधिकण को अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की है कि यह महज एक बालू का टीला है, जो समय के साथ यहां–वहां हो सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। कृष्णन ने कहा कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि रामसेतु भूगर्भीय, आंतरिक संरचना और सामुद्रिक विभाजक का काम करता है। विभिन्न भूगर्भीय और सामुद्रिक हलचलों को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि राम सेतु समुद्र को तोड़े जाने से समुद्र के भीतर भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। दुर्लभ जीव–जंतुओं के आवास समाप्त हो जाएंगे। और भारत से लगे समुद्रों में मानसून चक्र भी प्रभावित होगा। नतीजतन बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। हर साल बंगाल की खाड़ी में आने वाले खतरनाक तूफानों से राम सेतु ही बचाता है जिस कारण मन्नार की खाड़ी में असंतुलन की स्थिति नहीं आती है। इसलिए हम लोग भी वैज्ञानिकों के अनुसंधान से यह निष्कर्ष पा रहे हैं कि रामसेतु के कारण सुनामी को भी कमजोर होना पड़ा है। नहीं तो अब तक के अनुभवों के

मुकाबले सुनामी के कारण भयंकर क्षति हो जाती। रामसेतु को तोड़े जाने से ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगली सुनामी से केरल में तबाही का जो मंजर होगा उससे बचाना मुश्किल हो जाएगा। हजारों मछुआरे बेरोजगार हो जाएँगे।

सेतु समुद्रम परियोजना

ब्रिटिश शासन काल में सन् 1860 से इस योजना पर विचार चल रहा है। कई कमेटियां, समितियों, विद्वानों ने समेत सभी ने रामसेतु को तोड़ने के विकल्प को इस देश के लिये घातक बताया। परन्तु सन् 1955 में डॉ. रामास्वामी मुद्लियर समिति ने इसे उपयुक्त बताया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 13 मार्च 2003 को इस योजना की स्वीकृति दी। रामसेतु समुद्र दोनों देशों की ऐतिहासिक विरासत है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। 23 जून 2005 को अमेरिकी नौसेना ने इस समुद्र को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र घोषित कर दिया और तूतिकोरन पोर्ट ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष रघुपति ने 30 जून 2005 को गोलमोल ढंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके दो दिन पश्चात् ही 2 जुलाई 2005 को भारत के प्रधानमंत्री व जहाजरानी मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और करुणानिधि को साथ लेकर आनन–फानन में परियोजना का उद्घाटन कर दिया। इससे सरकार पर अमेरिकी हितों के लिये राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा।

भारत सरकार ने 2005 में सेतुसमुद्रम परियोजना की घोषणा की। इसकी लम्बाई 167 किलोमीटर, चौड़ाई 300 फीट गहराई, 12 मीटर पर अनुमानित लाग 2400 करोड़ लागत वृद्धि लगभग रुपए 400 करोड़। इस नहर से मालवाहक जहाज नहीं जा सकेंगे। जो जहाज इसका उपयोग करेंगे वे एक पायलट जहाज की सहायता से जिसका प्रतिदिन करीब 30 लाख रुपए तक व्यय होगा। यात्रा में 30 घंटे बचेंगे। रामेश्वरम् देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बन जाएगा। तमिलनाडु के तटीय इलाको का अधिक तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा। तूतिकोरेन हार्बर एक नोडल पोर्ट में तब्दील हो जाएगा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कम से कम 13 छोटे एयरपोर्ट बन जाएंगे। अनुमान है कि इसमें 2000 या इससे अधिक जल–पोत प्रतिवर्ष इस नहर से गुजरेंगे। 22 हजार करोड़ का तेल बचेगा। 19वे वर्ष तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय होगा।

इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट दायर की गई। इसके उत्तर में भारत सरकार ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। जिसके विरूद्ध पूरे देश में आंदोलन हुआ। जिससे घबराकर सरकार ने इसको वापिस लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना पर रोक लगाकर, इस योजना के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने का आदेश दिया। जिस पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

कनाड़ा के सुनामी विशेषज्ञ प्रो. ताड़मूर्ति ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि 2004 में आई विनाशकारी सुनामी लहरों से केरल की रक्षा रामसेतु के कारण ही हो सकी थी। बड़े मालावाह जहाज इसमें नहीं चल पाएंगे। मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। कोरल रीफ जैसे समुद्री जीव जंतुओं को भी क्षति होगी। दुर्लभ शंख व सीपों से सालाना होने वाली 150 करोड़ रुपए की आय भी समाप्त हो जाएगी। जल जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां समाप्त हो जाएगी।

कोस्टगार्ड के डायरेक्टर जनरल आर.एफ. कान्ट्रेक्टर ने 2007 में कहा था कि यह प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है।

अन्य विकल्प मार्ग

रामसेतु को नुक्सान पहुँचाए बिना भी अन्य वैकल्पिक मार्ग हैं :–

(1) तुतिकोरन बंदरगारह से मंडयम से पाक जल डमरू तक।
(2) तुतिकोरन बंदरगाह से पंपन के रास्ते पाक जल डमरू तक।
(3) तुतिकोरन बंदरगाह से रामेश्वरम् के रास्ते पाक जल डमरू तक।
(4) तुतिकोरन बंदरगाह से धनुकोष्टि के रास्ते पाक जल डमरू तक।
(5) तुतिकोरन बंदरगाह से धनुकोष्टि के बाहर से पाक जल डमरू तक।

एक प्रश्न यह भी है कि प्रधानमंत्री ने मार्च 2005 में तुतिकोरन बंदरगाह अथारटी से 16 प्रश्नों का जवाब मांगा था। फिर ऐसा क्या हो गया कि जवाब देखने से पहले ही 2 जुलाई 2005 को परियोजना का उद्घाटन करने पहुंच गए। वही बताया तो यह भी जा रहा है कि इसके लिए पंपन और धनुषकोटि के बीच 15 किलोमीटर की मुख्य भूमि में खुदाई कर स्वेज और पनामा की तरह जलमार्ग बनाया जा सकता है। वह भी बगैर प्रागैतिहासिक धरोहर को नष्ट किए।

हमारा उत्तरदायित्व

रामसेतु हमारी आस्था, विश्वास, प्रेम, प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय संस्कृति का ध्वज वाहक है। विश्व के करोड़ों लोगों का पूजनीय आदरणीय स्थल है। भारतीयों की आत्मा है। इसकी रक्षा करना हमारा उत्तरादायित्व व कर्तव्य है। ❑

हमारे दर्शन में है भारत के पतन की जड़ें

कैसे समझा जाये कि ब्रह्म क्या चाहता है? उपनिषदों में लिखा है कि पूर्व में ब्रह्म अकेला था। उसने सोचा ''मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाऊं।'' यानि अनेकता ही ब्रह्म की इच्छा थी जैसे अनेकों प्रकार के पशु पक्षी और पेड़–पौधे हैं। लेकिन अनेकता कष्टप्रद होती है जैसे भाई–भाई अपने को अलग मानने लगें तो वैर करते हैं। अपने को एक परिवार का माने तो मित्रता और प्रसन्नता रहती है। मेरी समझ में मूल समस्या है कि व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझने लगता है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

अर्थषास्त्री एन्गस मेडीसन ने अनुमान लगाया है कि आज से हजार वर्ष पूर्व यानि 1000 ई0 में विश्व की आय में एशिया का हिस्सा 67 प्रतिशत था और यूरोप का 9 प्रतिशत। वर्ष 1998 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। एशिया का हिस्सा घटकर 30 प्रतिशत रह गया था जबकि यूरोप का बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया था। एशिया के पतन में भारत का विशेष योगदान रहा है चूंकि एशिया में भारत का हिस्सा लगभग आधा था। यह पतन लगभग 1000 ई0 के बाद शुरू हुआ है। इसके पहले लगभग 4000 वर्षों तक हम समृद्ध थे। सिंधु घाटी, महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ, बौद्धकालीन लिच्छवी, मौर्य, विक्रमादित्य, गुप्त, हर्ष एवं चालुक्य साम्राज्यों ने हमें निरन्तर समृद्धि प्रदान की थी। इन 4000 वर्षों में हमारे प्रमुख ग्रन्थ जैसे वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत की रचना हो चुकी थी। अतः मानना चाहिये कि इन ग्रन्थों ने हमारे समाज को आध्यात्मिक उन्नति के साथ–साथ आर्थिक समृद्धि और राजनैतिक वैभव का मंत्र दिया था।

वर्ष 1000 के बाद महमूद गजनी, मुगल एवं ब्रिटिश लोगों ने हम पर धावा बोला और हमें परास्त किया। विचार करने वाली बात है कि 1000 के लगभग ऐसा क्या हुआ कि 4000 वर्षों से समृद्ध सभ्यता एकाएक अधोगामी हो गयी? प्रतीत होता है कि शंकर के दर्शन के गलत प्रतिपादन

के कारण यह हुआ। शंकर के समय को लेकर विद्वानों में विवाद है। कुछ का मानना है कि वे 800 ई0 के लगभग हुये थे। दूसरे विद्वानों का मानना है कि वे इससे बहुत पहले हुये थे। इस विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि वर्ष 800 के लगभग आदिशंकर स्वयं अथवा उनके किसी विषेष शिष्य ने इस धरती पर भ्रमण किया था।

उपलब्ध विषय के लिये शंकर का मुख्य मंत्र ''ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या'' है। शंकर ने सिखाया कि यह जो सम्पूर्ण जगत दिख रहा है यह एक ही शक्ति का विभिन्न रूपों में प्रस्फुटन है। मनुष्य स्वयं भी उसी एक ब्रह्म का स्वरूप है। अतः मनुष्य को चाहिये कि इन सांसारिक प्रपंचों में लिप्त होने के स्थान पर उस एक ब्रह्म से आत्मसात करे। तब उसे वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म से आत्मसात

वर्तमान में भारत दबाव में है। कुछ वर्ष पूर्व भारत को नई शक्ति के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन आज हम फिसल रहे हैं। इसका मूल कारण है देश के नेता अपने व्यक्तिगत हित साधने में लिप्त हैं। उन्हें राष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरत है कि सृष्टि की सत्यता को स्वीकार किया जाये। शंकराचार्य के मंत्र को 'सृष्टि सत्यं व्यक्ति मिथ्या' के रूप में समझना चाहिये न कि 'ब्रह्म सत्यं सृष्टि मिथ्या' के रूप में।

करने पर व्यक्ति ब्रह्म की इच्छानुसार व्यवहार करेगा जैसे कम्पनी में नौकरी स्वीकार करने के बाद व्यक्ति मालिक की इच्छानुसार व्यवहार करता है। अगला प्रश्न उठता है कि ब्रह्म क्या चाहता है? यदि ब्रह्म निष्क्रिय और अंतर्मुखी है तो साधक को भी निष्क्रिय और अंर्तमुखी हो जाना चाहिये। इसके विपरीत यदि ब्रह्म सक्रिय है तो मनुष्य को उसके चाहे अनुसार सक्रिय रहना चाहिये।

कैसे समझा जाये कि ब्रह्म क्या चाहता है? उपनिषदों में लिखा है कि पूर्व में ब्रह्म अकेला था। उसने सोचा ''मैं अकेला हूं, अनेक हो जाऊं।'' यानि अनेकता ही ब्रह्म की इच्छा थी जैसे अनेकों प्रकार के पशु पक्षी और पेड़–पौधे हैं। लेकिन अनेकता कष्टप्रद होती है जैसे भाई–भाई अपने को अलग मानने लगें तो वैर करते हैं। अपने को एक परिवार का माने तो मित्रता और प्रसन्नता रहती है। मेरी समझ में मूल समस्या है कि व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझने लगता है। सम्पूर्ण सृष्टि से वह नहीं जुड़ पाता है। संसार की अनेकता कष्टप्रद हो जाती है। एक उदाहरण से समझें। क्रिकेट टीम का हर खिलाड़ी टीम को जिताने के लिये खेले तो टीम जीतती है और वहद भी। इसके विपरीत यदि बालर या विकेट कीपर अपनी विशेषता को दिखाना चाहे तो टीम में कलह उत्पन्न होता है और टीम हारती है। शंकर ने इस समस्या का हल '' ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या '' के रूप में निकाला। अथवा कहा जाये कि ' टीम सत्यम व्यक्ति मिथ्या' तो बात बन जाती है। टीम का हर प्लेयर सम्पूर्ण टीम के हित में कार्य करने लगता है। जैसे कहा जाये 'परिवार सत्यं, व्यक्ति मिथ्या' तो परिवार सुखी हो जाता है क्योंकि हर सदस्य परिवार के हित को देखता है। लेकिन यदि कहा जाए कि ''ब्रह्म सत्यं, परिवार मिथ्या'' तो परिवार का हर सदस्य अपने को देखने लगेगा चूंकि परिवार के बंधन से वह मुक्त हो जायेगा। इसी प्रकार ''ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या'' का अर्थ है कि जगत के विभिन्न आकर्षणों को मिथ्या समझ कर सम्पूर्ण जगत के हित के लिये कार्य करें। इस भावना को जन में बैठाने के लिये शंकर ने कहा कि समझ लो कि तुम हो ही नहीं और जो भी है वह सम्पूर्ण सृष्टि है। अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन में शंकर सदा सक्रिय रहे–बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त किया, मंदिरों का उद्धार किया, उपनिषदों पर टीका लिखी और चार मठ स्थापित किये। यदि जगत मिथ्या था तो इन कार्यों को करने की क्या आवश्यकता थी?

1000 ई0 के बाद भूल यह हुयी है कि 'जगत मिथ्या' के मंत्र को शंकर के अनुयायियों ने परम सत्य मान लिया। वे भूल गये कि सम्पूर्ण जगत ब्रह्म है। अतः यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य ही है। जैसे भाई कहे कि परिवार मिथ्या है और कमाना बन्द कर दें तो परिवार दुखी होता है। इसी प्रकार शंकर के अनुयायी जगत को मिथ्या बताकर निष्क्रिय हो गये।

1000 ई0 के बाद भूल यह हुयी है कि 'जगत मिथ्या' के मंत्र को शंकर के अनुयायियों ने परम सत्य मान लिया। वे भूल गये कि सम्पूर्ण जगत ब्रह्म है। अतः यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य ही है। जैसे भाई कहे कि परिवार मिथ्या है और कमाना बन्द कर दें तो परिवार दुखी होता है। इसी प्रकार शंकर के अनुयायी जगत को मिथ्या बताकर निष्क्रिय हो गये। जब देश पर आक्रमण हो रहे थे तब ये अनुयायी कन्दराओं में बैठकर ब्रह्म से एका कर रहे थे। मेरे आकलन में 1000 ई0 के बाद भारत के पतन का यही प्रमुख कारण था।

'जगत मिथ्या' के मंत्र का एक और दुष्प्रभाव हुआ है। जगत मिथ्या हो जाने के बाद बचा मैं। 'मैं' स्वतंत्र हो गया। उसे जगत के हित और अहित को देखने की चिन्ता नहीं रही। जगत यानि गरीब मरता है तो मरने दो। इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है चूंकि गरीब वास्तव में है ही नहीं। आज देश के नेताओं के लिये एकमात्र अपने हित को साधना स्वीकार हो गया है। व्यक्तिवादी उपभोग हेतु प्रकृति यानि जल, जंगल, जमीन का अतिदोहन सृष्टि की उपेक्षा ही है। ऐसा आर्थिक विकास हमें दीर्घकाल में गहरे संकट में डालेगा। बड़ी कम्पनियों के द्वारा गरीब जुलाहे का रोजगार छीन लिया गया है और हमारे धर्म गुरू चुप बैठे हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं।

वर्तमान में भारत दबाव में है। कुछ वर्ष पूर्व भारत को नई शक्ति के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन आज हम फिसल रहे हैं। इसका मूल कारण है देश के नेता अपने व्यक्तिगत हित साधने में लिप्त हैं। उन्हें राष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरत है कि सृष्टि की सत्यता को स्वीकार किया जाये। शंकराचार्य के मंत्र को 'सृष्टि सत्यं व्यक्ति मिथ्या' के रूप में समझना चाहिये न कि 'ब्रह्म सत्यं सृष्टि मिथ्या' के रूप में। मेरा मानना है कि उक्त परिवर्तन करने पर देश की दबी हुयी ऊर्जा प्रस्फुटित हो जाएगी और हम विश्व में अपना उचित स्थान हासिल कर लेंगे।❑

बिलबिलाएं नहीं संयम से लें काम

पाकिस्तान की फौज ने पहले हमारे दो जवानों के सिर काट लिए और अब पांच जवानों की हत्या कर दी। हम क्या करें? अब हमारी सरकार क्या करे? सारा देश गुस्से में बिलबिलाया पड़ा है। पाकिस्तान से ज्यादा लोगों का गुस्सा भारत सरकार पर है। संसद ठप्प हो गई और अखबार व टीवी चैनल आग उगल रहे हैं।

■ **डॉ. वेदप्रताप वैदिक**

पाकिस्तान की फौज ने पहले हमारे दो जवानों के सिर काट लिए और अब पांच जवानों की हत्या कर दी। हम क्या करें? अब हमारी सरकार क्या करे? सारा देश गुस्से में बिलबिलाया पड़ा है। पाकिस्तान से ज्यादा लोगों का गुस्सा भारत सरकार पर है। संसद ठप्प हो गई और अखबार व टीवी चैनल आग उगल रहे हैं। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करने की बात एकदम बंद की जाए। ये आवाजें बिल्कुल स्वाभाविक हैं लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान के साथ इस वक्त दो–दो हाथ कर लिए जाएं? हमारे पांच जवानों के बदले हम पाकिस्तान के 50 जवानों को मौत के घाट उतार सकते हैं।

सितंबर में होने वाली दोनों प्रधानमंत्रियों की भेंट को रद्द कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा क्या कर लेगा? जाहिर है कि वह भारत के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ सकता, क्योंकि उसकी सेना का मनोबल आजकल काफी गिरा हुआ है, वह भयंकर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, आतंकवादियों ने भारत से ज्यादा पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा है, वहां नए राष्ट्रपति और सेनापति कुछ ही हफ्तों बाद नियुक्त होने वाले हैं और नई सरकार ने अभी–अभी तख्त सम्हाला है। ऐसी हालत में यदि भारत चाहे तो छोटा–मोटा बदला जरूर निकाल सकता है।

लेकिन हम जरा याद रखें कि प्रथम विश्वयुद्ध कैसे शुरु हुआ था। यूरोप के सिरायेवो नामक जगह में राजकुमार फर्डीनेंड की हत्या भर ने सारे विश्व को युद्ध में झोंक दिया था। भारत और पाक, दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। हमें अतिवाद से बचना होगा। इसके अलावा अभी तक यही ठीक से पता नहीं है कि सीमा पर गलती किसने की है? हमारी फौज का कहना है कि उसने पिछले दो माह में 19 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है और पिछले हफ्ते पांच पाकिस्तानी जवानों को मारा है।

हम जरा याद रखें कि प्रथम विश्वयुद्ध कैसे शुरु हुआ था। यूरोप के सिरायेवो नामक जगह में राजकुमार फर्डीनेंड की हत्या भर ने सारे विश्व को युद्ध में झोंक दिया था। भारत और पाक, दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। हमें अतिवाद से बचना होगा।

हमारे रक्षा मंत्री की भी जुबान अटक रही है। उन्हें पता ही नहीं कि वे लोग पाकिस्तानी आतंकवादी थे या फौजी जवान थे? ऐसी हालत में हमारी खबरपालिका और विधानपालिका, दोनों से संयम की आशा करना अनुचित नहीं होगा। टीवी चैनलों पर अधकचरे समीक्षकों की बाढ़ आई हुई है। वे एक–दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तिल का ताड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करते। क्या उन्हें सीमांत की झड़पों के बारे में हमारी फौज से भी ज्यादा जानकारी होती है?

मियां नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बातचीत भंग नहीं करनी चाहिए। बल्कि बातचीत को ज्यादा बढ़ाना चाहिए और इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। ❑

कहीं सूखा - कहीं बाढ़ क्यों?

हकीकत यह है कि यह स्थिति वर्षा की प्रवृत्ति में हुए कुछ बदलावों व भूमि प्रबंधन को गलत ढंग से बदलने में मनुष्य की गलतियों का मिला–जुला नतीजा है। वर्षा की प्रवृत्ति में बदलाव जलवायु बदलाव की व्यापक समस्या से जुड़ा मसला है। इसके लिए विश्वव्यापी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

■ **भारत डोगरा**

यह इन दिनों बार–बार देखा जा रहा है कि सूखे की स्थिति को बाढ़ की स्थिति में बदलने में देर नहीं लगती है। कई स्थानों में जहां पहले सूखे की स्थिति पर चिंता प्रकट की जा रही थी, वहां कुछ ही समय बाद देखा गया कि लोग बाढ़ या जल–जमाव की समस्या से त्रस्त हैं।

सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या यह स्थिति प्राकृतिक प्रकोप के कारण उत्पन्न होती है या इसमें मनुष्य की गलतियों का भी योगदान है?

हकीकत यह है कि यह स्थिति वर्षा की प्रवृत्ति में हुए कुछ बदलावों व भूमि प्रबंधन को गलत ढंग से बदलने में मनुष्य की गलतियों का मिला–जुला नतीजा है। वर्षा की प्रवृत्ति में बदलाव जलवायु बदलाव की व्यापक समस्या से जुड़ा मसला है। इसके लिए विश्वव्यापी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक अनुचित भूमि प्रबंधन का सवाल है, उसे हम अपने स्तर पर भी सुधार सकते हैं। जब काफी समय तक वर्षा न होने के कारण धरती सूखी और प्यासी होती है, तब सामान्यतरू यह उम्मीद रहती है कि बहुत वर्षा होने पर भी यह जल प्यासी धरती में समा जाएगा या खाली हो रहे जल स्नोतों मसलन तालाबों, पोखरों, झीलों आदि को भर देगा।

इस स्थिति में बाढ़ और जल–जमाव की समस्या उत्पन्न होने की आशंका कम होती है, लेकिन भूमि और जल प्रबंधन की गलतियों के कारण अधिक वर्षा केपानी का धरती व दूसरे जल–स्नोतों में समा जाने की आशंका कम हो गई है। अगर धरती पर हरियाली अधिक रहेगी तो पत्तों, टहनियों, घास, झाड़ियों आदि के रक्षा कवच से छनकर मूसलाधार वर्षा का पानी भी धरती पर कम वेग से गिरेगा और इसके धरती में समाने की क्षमता अधिक होगी। दूसरी ओर हरियाली नहीं होगी तो यह पानी धरती में कम समाएगा और तेज वेग से धरती पर उफनता हुआ बहेगा, जिससे बहुत–सी मिट्टी भी कटकर साथ बहेगी। इस तरह मिट्टी का तेज कटाव कर बहता हुआ पानी बाढ़ की आशंका को बढ़ाता है। यदि हरियाली कम होगी या अन्य कारणों से मिट्टी में जहरीले रसायनों विशेषकर

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अधिक देखने को मिलता है जबकि यह महानगर पहले ही जल संकट व तेजी से गिरते भूजल स्तर से त्रस्त हैं। इतना ही नहीं, नदियों के पेट से बालू–रेत निकालने की प्रवृत्ति अब तेजी से देशभर में फैल रही है। पर्यावरण को बर्बाद करने वाले इस धंधे से अब तमाम बड़े व खतरनाक माफिया जुड़ गए हैं जो गांववासियों की तो क्या अधिकारियों तक की परवाह नहीं करते हैं?

कीटनाशकों के कारण मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीव बहुत कम बचेंगे तो मिट्टी का भुरभुरापन, जल तथा नमी संरक्षण करने की उसकी क्षमता भी कम होगी। यह सब हमारे देश में जगह–जगह हो रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार घटते वन के कारण भूस्खलन व बाढ़ का खतरा दिनोंदिन अधिक बढ़ रहा है। इससे प्रकृति का संतुलन प्रभावित होता है और मानवजाति को भी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। भूस्खलन से जो नुकसान होता है वह तो होता ही है, साथ ही यह बाढ़ का प्रकोप बढ़ाने का कारण भी बनते हैं। शहरी क्षेत्रों में बिना जरूरत के भी जगह–जगह सीमेंट की परत बिछा देने से धरती की वर्षा का पानी ग्रहण करने की क्षमता काफी घट गई है। हर जगह सीमेंट–कंक्रीट बिछाना उतना जरूरी है नहीं जितना मान लिया गया है। यहां तक कि पेड़ों के आसपास भी सीमेंट–कंक्रीट लगा दी जाती है जिससे पेड़ सूखने लगते हैं।

सबसे बुरी स्थिति तो नदियों के आसपास की है जहां धरती द्वारा जल ग्रहण के सबसे अनुकूल क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने के निर्माण कार्य कर यहां भू–जल संरक्षण की संभावना को न्यूनतम कर दिया जाता है। ऐसा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अधिक देखने को मिलता है जबकि यह महानगर पहले ही जल संकट व तेजी से गिरते भूजल स्तर से त्रस्त हैं। इतना ही नहीं, नदियों के पेट से बालू–रेत निकालने की प्रवृत्ति अब तेजी से देशभर में फैल रही है। पर्यावरण को बर्बाद करने वाले इस धंधे से अब तमाम बड़े व खतरनाक माफिया जुड़ गए हैं जो गांववासियों की तो क्या अधिकारियों तक की परवाह नहीं करते हैं? प्रतिदिन लाखों रुपये कमाने वाले ये माफिया बहुत बेदर्दी से भारी–भरकम मशीनों को नदी में तैनात कर उसके गर्भ से प्रतिदिन टनों रेत बालू निकालते हैं। इस तरह के रेत में पानी को संरक्षित करने की काफी अधिक क्षमता होती है जिससे न केवल सूखे मौसम में भी नदी का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलती है, अपितु आसपास के कुंओं का जलस्तर भी ठीक बना रहता है। जहां रेत बड़े पैमाने पर निकाल ली जाती है, वहां नदी सूखने लगती है।

हाल के वर्षों में इन जल स्रोतों को न केवल निर्माण कार्यों या खेती आदि के लिए पाटा गया, बल्कि उनके जल ग्रहण क्षेत्रों व मार्गों को भी अवरुद्ध कर दिया गया। इससे वर्षा का पानी अन्य जलस्नोतों की ओर न बहकर जगह–जगह बाढ़, जल–जमाव व दलदलीकरण के रूप में तबाही मचाता है।

दूसरी ओर वर्षा के समय रेत के माध्यम से जल संरक्षण न होने के कारण बाढ़ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ट्रकों और भारी मशीनों के बार–बार नदियों तक जाने से जो राह बनती है, उससे आबादी की ओर तेजी से बाढ़ का पानी बहने की संभावना और बढ़ जाती है। धरती पर बहुत–सी प्राकृतिक झील, तालाब, पोखर, जोहड़ आदि प्राकृतिक तौर पर मौजूद रहे हैं, जहां निचले स्थानों पर अपने प्राकृतिक बहाव से वर्षा का पानी खुद ब खुद एकत्र होता रहा है। इसके अतिरिक्त अपने उद्यम से भी मनुष्य ने बहुत से तालाब व झीलों आदि का निर्माण किया है। इस तरह के जल स्रोतों का निर्माण करते समय अच्छा जलग्रहण क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वर्षा के समय में इनमें बहुत सा पानी एकत्र हो सके। इन जल–स्रोतों में वर्षा का पर्याप्त पानी पहुंचता रहे तो एक ओर बाढ़ की संभावना कम होती है और दूसरी ओर सूखे महीनों के लिए जल संरक्षित होता है।

हाल के वर्षों में इन जल स्रोतों को न केवल निर्माण कार्यों या खेती आदि के लिए पाटा गया, बल्कि उनके जल ग्रहण क्षेत्रों व मार्गों को भी अवरुद्ध कर दिया गया। इससे वर्षा का पानी अन्य जल स्रोतों की ओर न बहकर जगह–जगह बाढ़, जल–जमाव व दलदलीकरण के रूप में तबाही मचाता है। विभिन्न निर्माण कार्यों में जल्दबाजी या लापरवाही के कारण और उससे भी अधिक पैसे बचाने व भ्रष्टाचार के कारण प्रायः निकासी के रास्तों की अवहेलना होती है। इससे पानी का निर्बाध बहाव प्रभावित होता है और जो बाढ़ का पानी कुछ घंटों में निकल जाता था वह अब कई सप्ताह तक जमा रहता है। बड़े निर्माण कार्यों के दौरान भूमि की ढलान में जो बदलाव होते हैं, उसके कारण भी कई नए स्थानों में जल–जमाव की समस्या देखने को मिलती है। भूमि की विषमता भरे वितरण के कारण अनेक निर्धन परिवारों को निचले स्थानों पर नदी–नालों के किनारे बसना पड़ता है और साथ ही बाढ़ का अधिक प्रकोप डोलना पड़ता है।

इन तमाम मानव निर्मित कारणों के अतिरिक्त कम समय में अधिक वर्षा होने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। जलवायु बदलाव के जानकार बताते हैं कि इस दौर में यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ते की पूरी आशंका है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि जिन गलतियों को सुधारना हमारे नियंत्रण में है कम से कम उस ओर पूरा ध्यान दें ताकि सूखे व बाढ़ दोनों से एक साथ राहत मिल सके। ❑

रपट

डेयरी क्षेत्र को बचाने की दरकार

लगभग दो वर्षों से भारत सरकार यूरोपीय देशों के साथ एक व्यापार संधि करने के प्रयास में जुटी है जिसके अनुसार यूरोप से दुग्ध उत्पादन पर आयात शुल्क शून्य हो जाएंगे। गौरतलब है कि यूरोपीय समुदाय के देश अपने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान करते हैं। ऐसे में सब्सिडी युक्त दुग्ध उत्पादों के भारत में खुले प्रवेश के बाद किसान को मिलने वाले दूध की कीमत एकदम नीचे आ जाएगी। ऐसे में दुग्ध उत्पादक किसान जो पहले से ही भारी लागत की मार झेल रहा है, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा और देश आयातित दुग्ध उत्पादों पर निर्भर हो जाएगा।

भारत में डेयरी विकास के लिए नीतिगत सुझावों पर चर्चा करने के लिए अहमदाबाद में अमूल के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 31 जुलाई 2013 को किया गया। संगोष्ठी में अमूल के अध्यक्ष श्री विपुल चौधरी, प्रबंधक निदेशक श्री आर.एस सोढ़ी, भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनकड़, गुजरात प्रदेश के पूर्व वित्तमंत्री श्री सनत मेहता, स्वदेशी जागरण मंच केन्द्रीय टोली के सदस्य डॉ. अश्विनी महाजन के अतिरिक्त गुजरात सरकार के सचिव श्री डी.एच. बह्म भट्ट, जाने–माने अर्थशास्त्री डॉ. हेमन्त कुमार शाह और डेयरी क्षेत्र से जुड़े 40 से भी अधिक महानुभावों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी की प्रमुख विशेषताएं ये थी कि सहकारिता क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के डेयरी उद्यमों ने भी हिस्सा लिया। मधुसूदन घी के प्रबंध निदेशक श्री संदीप अग्रवाल और क्वालिटी डेयरी के श्री संजीव नेगरा ऐसी कुछ नाम थे।

डेयरी क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करने के अतिरिक्त भविष्य में डेयरी विकास के मार्ग में आने वाले बाधाओं पर विस्तार में चर्चा हुई। बढ़ती लगातों पर चिंता व्यक्त की गई और डेयरी विकास के प्रणेता श्री कुरियन के बाद डेयरी क्षेत्र के नेतृत्व में स्थिरता लाने की जोरदार पैरवी की गई। श्री आर.एस. सोढ़ी ने अपने वक्तव्य में देश में डेयरी विकास, क्षमताओं और भविष्य की चिंताओं पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने यूरोपीय समुदाय के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से डेयरी विकास में आने वाली बाधाओं और समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। संगोष्ठी में आए विचारों के आधार पर एक नीतिगत पत्र तैयार किया गया। जिसमें दूसरी दुग्ध क्रांति के लिए रोड मैप की चर्चा के अतिरिक्त सरकार की नीति में खामियों की ओर संकेत किए गए हैं। दूध को कृषि उत्पाद मानते हुए डेयरी क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस नीति पत्र में डेयरी को आय कर से भी मुक्त करने की भी मांग की गई है। डेयरी क्षेत्र को नरेगा में शामिल करने के अलावा बढ़ते पशु आहार की कीमतों पर भी चिंता व्यक्त की गई है। लोगों की खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पशुओं की चारे की सुरक्षा की मांग भी इस पत्र में की गई है। दूध को मिड डे मील का हिस्सा बनाया जाए, सहकारी संस्थाओं को सरकार का सहयोग मिले, सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता का दर्जा मिले और राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड की स्थापना हो। ऐसी मांग इस नीति पत्र में की गई है।

यूरोपीय समुदाय के साथ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में नीतिगत पत्र में कहा गया है कि यूरोपीय समुदाय के देश डेयरी क्षेत्र को भारी आर्थिक सहायता देते हैं, जिसके कारण वहां के डेयरी उत्पादकों के आयात खुलने से भारत के डेयरी क्षेत्र बर्बाद हो सकता है। ऐसे में नीतिगत पत्र में मांग की गई है कि इस समझौते को करते हुए सरकार बेहद सतर्क रहे। साथ ही यह भी मांग की गई है कि भविष्य में डेयरी क्षेत्र के उत्पादकों पर आयात शुल्क घटाने से पहले डेयरी क्षेत्र के लोगों से व्यापाक विचार विमर्श किया जाए।

देश जब आजाद हुआ तो उस समय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 129 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। आज प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 233 ग्राम प्रतिदिन पहुंच चुकी है। वास्तव में देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि 1970 के दशक से प्रारंभ हुई। गौरतलब है कि एक विशेष कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया, जिसका नाम था 'आपरेशन फ्लड'। दुग्ध उत्पादन में कम समय में इतनी भारी वृद्धि को श्वेत क्रांति का भी नाम दिया जाता है। देश में 'मिल्कमैन' के नाम से जाने जाने वाले डॉ. कोरियन इस श्वेत क्रांति के मुख वाहक बने। कुपोषण से लड़ता हुए इस देश में जहां प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता पिछले दो दशको में खासी कम हो चुकी है, एक ओर बढ़ते दुध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के कारण कुछ राहत जरूर दिखाई देती है।

किसान की आमदनी और महिला सशक्तिकरण

पिछले 4 दशको के दौरान डेयरी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के चलते किसान को भी लाभ पहुंचा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर दूध का उत्पादन प्रतिदिन 35 करोड़ लीटर पहुंच चुका है, जबकि वैश्विक उत्पादक 207 करोड़ लीटर का है। दुनिया में सर्वाधिक उत्पादन करना

वाला देश भारत है। वर्ष 2012–13 के दौरान देशभर से दूध उत्पादन का कुल मूल्य 4 लाख करोड़ रूपए आंका गया है। अगर किसी एक फसल के कुल मुल्य की तुलना दूध के कुल मुल्य से की जाए तो दूध का मुल्य ज्यादा होगा। भार की दृष्टि से देखा जाए, तो देश में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का होता है, जो 1040 लाख टन है। लेकिन दूध का उत्पादन उससे भी ज्यादा 1300 लाख टन तक पहुंच चुका है। इसका अभिप्राय यह है कि किसान को किसी एक फसल से ज्यादा आमदनी दूध उत्पादन से होती है।

साथ ही साथ डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान पुरूषों से कहीं ज्यादा है। सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के माध्यम से, जो दूध खरीदा जाता है, उससे महिलाओं के सशक्तिकरण में खासी प्रगति हुई है। उन्हें न केवल उपयोगी रोजगार मिला है, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा में भी भारी वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कि जहां 1980–81 में कृषि से कुल जीडीपी का 38 प्रतिशत प्राप्त होता था, जो घटकर 2012–13 में मात्र 13.6 प्रतिशत ही रह गया है। लेकिन कृषि के साथ जुड़ी हुई इस गतिविधि से 4 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हर वर्ष होता है। जाहिर है अगर डेयरी क्षेत्र में प्रगति न हुई होती, तो किसान का कृषि में रहना संभव ही नहीं होता। इसलिए देश की कृषि को बचाने का काम भी डेयरी क्षेत्र ने किया है।

सहकारिता ने किया सहयोग

देश में डेयरी क्षेत्र के विकास में सहकारिता आंदोलन और उसमें भी अमूल और मदर डेयरी मॉडल का योगदान सराहणीय कहा जा सकता है। आज देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं। संगठित क्षेत्र में अधिकतम योगदान सहकारी क्षेत्र का है और उसमें दुग्ध पुरुष (मिल्क मैन) डॉ. कुरियर के नेतृत्व मे अमूल मॉडल को आज दुनियाभर में सराहा जा रहा है। कई राज्यों में छोटे–छोटे दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध खरीदा जाता है और उसे बड़े–बड़े आधुनिकतम प्लांटों के माध्यम से परिष्कृत किया जाता है और उसमें मूल्य वृद्धि की जाती है। संगठित क्षेत्र की मदद से दुग्ध उत्पादक किसान को उपभोक्ता कीमत का तीन चौथाई से भी ज्यादा मिलता है, जो दुनियाभर में एक मिसाल है।

डेयरी क्षेत्र पर मंडराते खतरे

हालांकि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और किसान की आमदनी में भी खासा इजाफा हुआ है, फिर भी भारत सरकार मुक्त व्यापार के नाम पर ऐसे समझौते कर रही है, जिससे डेयरी क्षेत्र तबाह हो सकता है। डेयरी क्षेत्र की अपनी कई समस्याएं पहले से ही हैं, जिसमें पुरानी नस्लों के कारण प्रति पशु (गाय/भैंस) का अत्यंत कम दुग्ध उत्पादन, सरकारी नीति की उदासीनता, खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रमुख हैं। पिछले लगभग दो वर्षों से भारत सरकार यूरोपीय देशों के साथ एक व्यापार संधि करने के प्रयास में जुटी है जिसके अनुसार यूरोप से दुग्ध उत्पादन पर आयात शुल्क शून्य हो जाएंगे।

गौरतलब है कि यूरोपीय समुदाय के देश अपने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान करते हैं। ऐसे में सब्सिडी युक्त दुग्ध उत्पादों के भारत में खुले प्रवेश के बाद किसान को मिलने वाले दूध की कीमत एकदम नीचे आ जाएगी। ऐसे में दुग्ध उत्पादक किसान जो पहले से ही भारी लागत की मार झेल रहा है, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा और देश आयातित दुग्ध उत्पादों पर निर्भर हो जाएगा। किसान जो दुग्ध उत्पादकों से अपनी आमदनी बढ़ाता है, अब उसके लिए कृषि लाभ का सौदा नहीं रह जाएगा।

संगोष्ठी में विचार–विमर्श के बाद बने नीतिगत प्रपत्र में दिए गए सुझावों को अपनाने से ही देश के डेयरी विकास को एक मजबूत दिशा मिल सकेगी। ❑

किसानों को मिले अस्थायी बिजली कनेक्शन

4 अगस्त 2013 को स्वदेशी जागरण मंच (राजस्थान) की मासिक बैठक विभाग संयोजक अधिवक्ता लालूराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभाग संयोजक ने बताया कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से आज किसान खेती से विमुख होने को मजबूर हो चला है। अपनी ही उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से बिजली का बिल भी चुकाने में किसान असमर्थ होता जा रहा है। विभाग संयोजक ने राज्य सरकार से मांग कि वह अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी किसानों को अस्थाई कृषि कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बरसात और गर्मी के मौसम में किसानों को कृषि कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसानों को पूरे वर्ष बिजली का बिल भरना पड़ता है। जिससे पहले से ही आर्थिक बोझ तले दबे किसान पर और ज्यादा आर्थिक भारत बढ़ जाता है। उन्होंने किसानों की आवश्यकता अनुसार अस्थाई कृषि कनेक्शन दिए जाने की मांग की। बैठक में सह जिला संयोजक श्यामलाल धाकड़, पवन वैष्णव, रामलाल धाकड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ❑

एफडीआई की खुली छूट का निर्णय जन-विरोधी

रिटेल में एफडीआई के विरोध में देश व्यापारी संघर्ष की शुरूआत करेगा। राज्य की राजधानियों में धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो देश का व्यापारी लघु उद्योग वर्ग किसानों, मजदूरों, उपभोक्ताओं को साथ लेकर दिल्ली कूच करेगा।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने भारत सरकार द्वारा खुदरा व्यापार बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट देने की निंदा की है। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारत सरकार द्वारा विदेशी पूंजी को खुली छूट देने का निर्णय जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। सरकार ने फैसला किया है कि खुदरा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक की एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से आ सकती है। यह फैसला विदेशी पूंजी निवेश को बेलगाम कर देगा। जब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाई गयी थी तो वाणिज्य मंत्री ने लम्बे चौड़े वायदे किए थे कि देश का लघु उद्योग मजबूत होगा और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती आएगी। भारत सरकार के मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत देने के बावजूद अब तक कोई विशेष विदेशी निवेश नहीं हुआ है। विदेशी कंपनियों की मांग है कि शर्तों में ढील दी जाए।

वाणिज्य मंत्री के बयानों से यह लगता है कि वे शर्तों में ढील देने की तैयारी में लगे हैं। विदेशी कंपनियों की शर्तों के आगे झुकना सरकार की बेबसी को दिखाता है और भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल इसका पुरजोर विरोध करेगा। बीयूवीएम के राष्ट्रीय महामंत्री विजय प्रकाश ने ने बताया कि भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल नए सिरे से रिटेल में एफडीआई के विरोध में देश व्यापारी संघर्ष की शुरूआत करेगा। राज्य की राजधानियों में धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो देश का व्यापारी लघु उद्योग वर्ग किसानों, मजदूरों, उपभोक्ताओं को साथ लेकर दिल्ली कूच करेगा। **प्रस्तुति : ओम किशन गुप्ता**

देश की सुरक्षा को दांव पर न लगाए केन्द्र सरकार

चीन से अनावश्यक आयात बंद करने, निर्यात को बढ़ावा देने प्रोत्साहन योजना बनाने, प्रवासी भारतीयों को अपने देश में ज्यादा निवेश के लिए प्रेरित करने से विदेशी मुद्रा संकट का समाधान हो सकता है। जिससे प्रतिक्षा व दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी को तुरंत वापस लेने की जरूरत है।

स्वदेशी जागरण मंच (उड़ीसा) ने केंद्र की कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने प्रतिरक्षा और दूरसंचार में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने की देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का आरोप लगा दिया है। मंच ने 20 जुलाई को दोनों क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश वापस लेने की मांग पर बिक्षोभ प्रदर्शन किया। जिसमें यह मांग पूरी न होने से आगामी दिनों में जोरदार आंदोलन चलाने की चेतावनी यूपीए सरकार को दी।

20 जुलाई की शाम बिसरा चौक पर प्रतिवाद सभा तथा बिक्षोभ प्रदर्शन में मंच के रमाकांत पात्र, बाबाजी साहु, विवेकानंद महांत, राजेंद्र महांत, दिलीप पटनायक, हिमांशु बल, विष्णु महांत, ज्ञान मिश्र, राजेश हालदार, भरत गौड़, सत्यव्रत पंडा, जयंत प्रधान युधिष्ठिर महांत, विवेक साहू, सूरत पंडा, सुकांति सुतारि आदि ने विदेशी पूंजी निवेश से देश को होने वाले नुकसान पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 49 फीसदी तथा दूरसंचार में 100 फीसद विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह की अकर्मण्यता के कारण देश में अब केवल आठ महीनों के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार बचा है।

विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए इस सरकार ने देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगाने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि चीन से अनावश्यक आयात बंद करने, निर्यात को बढ़ावा देने प्रोत्साहन योजना बनाने, प्रवासी भारतीयों को अपने देश में ज्यादा निवेश के लिए प्रेरित करने से विदेशी मुद्रा संकट का समाधान हो सकता है। जिससे प्रतिरक्षा व दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी को तुरंत वापस लेने की जरूरत है। ❑

चीन की चुनौतियां

भारत के ऊपर चीन की ओर से तीन प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। पहला – सीमा सुरक्षा समस्या, दूसरा – वैचारिक समस्या, तीसरा आर्थिक सुरक्षा समस्या। – अनदा शंकर पाणिग्रही

दिनांक 6 जुलाई 2013 को स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर की और से स्थानीय तुलसी भवन में ''चीन की चुनौतियां'' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री अनदा शंकर पाणिग्रही, विशिष्ठ अतिथि पूर्व आरक्षी उपाधीक्षक श्री आर. दयाल, मंच के पूर्वांचल संघर्ष वाहिनी प्रमुख बंदेशंकर सिंह, मनोज कुमार सिंह और डॉ. अनिल राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री अनदा शंकर पाणिग्रही ने कहा कि भारत के ऊपर चीन की ओर से तीन प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। सीमा सुरक्षा समस्या, वैचारिक समस्या और आर्थिक सुरक्षा समस्या। देश के अंदर आज नक्सलवाद समस्या नहीं है, यह माओवादियों की समस्या है जिसका पोषक चीन है।

विशिष्ट अतिथि आर दयाल ने कहा कि चाईना हमारे देश के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक चारों ओर से आक्रमण कर रहा है हमें इससे बचना होगा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि चीन और भारत का संबंध लगभग 5000 वर्ष पुराना है लेकिन चीन इसे भुलाकर भारत के ऊपर समस्या बनता जा रहा है। वह देश के चारों ओर से घेर कर अपना सैनिक अड्डा बना लिया है, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर में कैरिडोर निर्माण के साथ–साथ हिन्द महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो, सभी जगह वह अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इसके साथ ही माओवाद के द्वारा हमारे ही देश के लोगों को बहलाकर देश के विरूद्ध खड़ा कर दिया और हमारे आंतरिक सुरक्षा में सेंध मार रहा है। वह हमारे देश के 33 प्रतिशत बाजारों पर कब्जा कर हमारे देश के लगभग 40 अरब डॉलर का व्यापार घाटा बढ़ा दिया है जो आर्थिक खतरे का संकेत है।

चीन और भारत का संबंध लगभग 5000 वर्ष पुराना है लेकिन चीन इसे भुलाकर भारत के ऊपर समस्या बनता जा रहा है।

गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए श्री बंदेशंकर सिंह ने भी चीन से उत्पन्न खतरे से लोगों को सचेत रहने की बात कही। इस गोष्ठी में डॉ. अनिल राय, अभय सिंह, राजपति देबी और चंदना बनर्जी ने भी अपने विचार रखें।

गोष्ठी का विषय प्रवेश विचार मंडल प्रमुख पंकज कुमार सिंह ने कराया। गोष्ठी का संचालन जिला संयोजक राजकुमार साह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अमित मिश्र ने किया। गोष्ठी को सफल बनाने में प्रमुख रूप से कौषल किशोर, आनन्द मजुमदार, रामेश्वर प्रसाद, अभिषेक बजाज, गौरव शंकर, राकेश पाण्डेय, गुरजीत सिंह, राकेश सिंह, रौशन सिंह, अरविन्द तिवारी, मिथलेश प्रसाद, अनिल तिवारी, ललित मेश्राम, पी. एन. दुबे, महाबीर बाग, सत्यनारायण मिश्र, संजीत प्रमाणिक, सुजय कुमार, सुशील झुनझुनवाला, अशोक गोयल, राजेश अग्रवाल, सुनिल गुप्ता, मो. अमान, देव कुमार अरविन्द प्रसाद, बिनोद ठाकुर, नवनीत सिंह, उपासना दत्ता सहित अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। – प्रस्तुति : राकेश कुमार पाण्डेय